www.cgfrontline.com

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

■ वर्ष: 01 ■ अंक: 87 ■ जशपुर, 22 नवंबर 2026 (रविवार) ■ पृष्ठ: 08 ■ मूल्य: 01 रूपये

दवा डीलर से लॉरेंस बिशोई के नाम पर 15 करोड़ रुपये, रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

दुर्ग। दवा वाणिज्य और मोक्षित कॉर्पोरेशन के निदेशक शशांक चोपड़ा से 15 करोड़ रुपए की फिरौती आतंकवाद का मामला सामने आया है। 19 नवंबर को उन्हें वॉट्सऐप पर धमकी भरा वॉइस नोट मिला। इसके साथ कॉल करके भी धमकाया गया। वॉइस नोट और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया कि रकम नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देंगे और वॉइस को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद वॉइस ने उसी दिन शाम को गन्ने के थाने में दस्ता दर्ज कराया। परिवार की सुरक्षा के लिए घर के बाहर तीन दिन से पुलिस तैनात है। मामला दुर्ग के गन्ने के थाना इलाके का है।

घर के बाहर पुलिस तैनात, नंबर की जांच जारी

शिकायत मिलने के बाद दुर्ग पुलिस ने मामले को देनदार से लिया है। वॉइस के घर के बाहर पुलिस की टीम तैनात की गई है। पुलिस वॉट्सऐप पर आए वॉइस मैसेज और कॉल और उससे जुड़े नंबर की जांच कर रही है। दूसरे तकनीकी सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता से इनकार किया है। जांच की जा रही है कि वॉइस मैसेज भेजने वाले का गैंग से वास्तव में कोई संबंध है या उसने सिर्फ नाम लेकर विक्रेताओं को डराने की कोशिश की है।

मेडिकल खरीद मामले में भी चर्चा में रहे हैं शशांक

शशांक चोपड़ा की फर्म मेडिकल उपकरण, जांच में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और स्वास्थ्य से जुड़े सामान उपलब्ध कराती है। उनका नाम छत्तीसगढ़ में मेडिकल उपकरण और री-एजेंट की खरीद से जुड़े कथित घोटाले में भी सामने आया था। इस मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जनवरी 2025 में केस दर्ज किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मांगे की जांच शुरू की। जांच पदार्थों ने खरीद में गड़बड़ी और सरकारी भंडार को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए थे। इस मामले में शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें अलग-अलग मामलों में कोर्ट से जमानत मिली।



36 हजार महिलाएं-बच्चियां लापता

7 हजार का अब तक नहीं मिला सुराग - कांग्रेस ने घेरा सरकार को

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राजधानी में नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त के मामले में सामने आए अंतरराज्यीय गिरोह और प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों की बढ़ती गुमशुदगी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर छापना साधा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि शिशुओं से नवजातों की खरीद-फरोख्त का मामला प्रशासनिक लापरवाही और संभावित मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि निजी शिशुओं में फर्जी रेन टिकट के जरिए 26 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए। आरोप के मुताबिक,



गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को छापकर नवजात बच्चों का सौदा 5 से 12 लाख रुपये तक में करता था।

36 हजार से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां लापता होने का दावा

प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की गुमशुदगी के आंकड़ों को चिंताजनक बताते हुए कांग्रेस ने सरकार पर संवेदनशील मामलों में देनदारी नहीं दिखाने का आरोप लगाया। सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि पिछले तीन सालों में 10,753 लड़कियां लापता हुईं, जबकि 11,825 को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच लापता 982 बच्चों में से 400 अब तक बरामद नहीं हुए हैं। इनमें 14 से 17 साल की किशोरों की संख्या ज्यादा बताई गई है। कांग्रेस के अनुसार, साल 2023 से जनवरी 2026 तक प्रदेश में कुल 36,662 महिलाएं और बच्चियां लापता हुईं, जिनमें से 7,188 का अब तक पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस ने सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर और बस्तर जैसे आदिवासी एवं सीमावर्ती जिलों को मानव तस्करी के एलएस से संवेदनशील बताए हुए सरकार से महिला सुरक्षा, मानव तस्करी की रोकथाम और लापता महिलाओं-बच्चियों की तलाश के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस ने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने और कानपुर, प्रशासनिक तंत्र तथा जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने सवाल उठाया कि बिना प्रसव के शिशुओं से फर्जी रेन टिकट और नगर निगम के रिकॉर्ड में मनोहर के नाम से जन्म प्रमाण-पत्र कैसे जारी हो रहे थे। कांग्रेस नेता के मुताबिक, गिरोह का नेटवर्क रायपुर और बिलासपुर से लेकर ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ था। उन्होंने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका की जांच कराने की मांग की।

भाजपा की किसानों के लिए 4 हितैषी योजनाएं, धान-गन और मिलेट्स

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



भिलाई। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और विभिन्न फसलों के बीजों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भाजपा ने चार किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी है। भिलाई स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश मुख्यालय अखिलेश सोनी ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। अखिलेश सोनी ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से धान के साथ-साथ गन्ना और मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को भी आर्थिक लाभ बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान उत्थान योजना के तहत अपने पंजीकृत रकबे की तुलना में कम धान बेचने वाले किसानों को भी निश्चित प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। इसके अलावा गन्ना उत्पादक किसानों, पीएम-आशा अभियान के तहत आने वाले किसानों और मिलेट्स फसल लेने वाले किसानों के लिए भी प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई गई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को ही मिल सकेगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जिससे किसानों का समय पर पंजीयन हो सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश सोनी ने कहा कि सभी प्रकार की फसल लेने वाले किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की गई हैं, ताकि किसानों को लागत की पूर्ति के साथ बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।

जशपुर के युवा अमेरिका में लगेंगे रॉक क्लाइंबिंग गाइड का प्रशिक्षण



❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। जिले के पांच आदिवासी युवाओं का अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था प्रोफेशनल क्लाइंबिंग गाइड्स इंस्टीट्यूट (PCGI) के अंतरराष्ट्रीय रॉक क्लाइंबिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। यह उपलब्धि जशपुर जिले को साहसिक पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशिक्षण के लिए युवाओं में तेजल भगत, रुसनाथ भगत, सचिन कुजूर, प्रतीक नायक और रवि सिंह शामिल हैं। इन युवाओं को दिसंबर माह में बेंगलुरु में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रॉक क्लाइबिंग की आधुनिक तकनीकें, सुरक्षा मानकों और पेशेवर गाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण भारत के प्रमुख रॉक क्लाइंबिंग आयोजनों में शामिल ROMP के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चार युवाओं को PCGI लेवल-1 तथा एक युवा को उन्नत लेवल-2 आवेदकों से मिलने की उम्मीद है।

इस पहल की सफलता के साथ जशपुर मध्य भारत का पहला ऐसा पर्यटन स्थल बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित रॉक क्लाइंबिंग गाइडों की समर्पित टीम उपलब्ध होगी। इससे जिले में साहसिक पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गाइड आवेदकों की सुविधा उपलब्ध होने के साथ जशपुर यह उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि दूरदर्शी प्रशासन और समुदाय की भागीदारी से किस तरह भारत को वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार होंगे स्थानीय गाइड

साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित गाइडों की उपलब्धता और सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों में तकनीकी दक्षता, सुरक्षा उपकरणों की जानकारी और जोखिम प्रबंधन की विशेष आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और आवेदकों की सीमित उपलब्धता भारत में साहसिक पर्यटन के विस्तार की जबड़े में शामिल हो रही है।

PCGI के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जशपुर के युवाओं को रॉक क्लाइंबिंग गाइडिंग की आधुनिक तकनीकें, सुरक्षा गतिविधियां और पेशेवर एथलीटों का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इससे जिले में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पेशेवर तरीकों से संचालित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं की तकनीकी क्षमता और रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

खर्चों के बैंकों की नीलामी जब्ती होगी, ब्लैकलिस्ट होंगे

लोनिवि के सचिव बंसल का तूफानी दौरा, सघन निरीक्षण के दौरान दिखा नरम-गरम तेवर

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने लगातार दो दिनों तक चार जिलों में सड़क, पुल-पुलिया, कॉलेज, अस्पताल और अन्य निर्माण कार्यों की ऊंची पड़ताल की। जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में मौके पर पहुंचकर उन्होंने काम की प्रगति और गुणवत्ता परखी। जहां फायरिंग मिली, वहां मौके पर ही सख्त निर्देश दिए।

काम और सड़क संधारण में फायरिंग पर ड्यूटी वालों को नोटिस जारी करने, बैंक गारंटी करने और सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने को कहा गया।

दौरे में प्रमुख अभियोक्ता व्ही.के. भतपहरी, अंबिकापुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियोक्ता के.पी. संत, अंबिकापुर मंडल के अधिक्षण अभियोक्ता आर.एस. तोमर तथा संबंधित संभागों के कार्यपालन अभियोक्ता, अनुविभागीय अधिकारी और ड्यूटी मौजूद रहे। टीम ने जशपुर, मनोरा, सन्ना, बगीचा, कांसाबेल, बागबहार, कोतबा, लुडगा, सीतापुर, पत्थलगांव, मैनपाट, दरिमा, राजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान और सूरजपुर में सड़कों की स्थिति और निर्माण कार्यों का ब्यौरा लिया।

दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर पर कार्रवाई

सरगुजा जिले में दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर मार्ग के निरीक्षण में संधारण अवधि में निर्धारितों द्वारा उचित रखरखाव नहीं किया जाने की स्थिति सामने आई। इस पर सचिव बंसल ने दोनों ऊंचाई के निर्धारितों की बैंक राजसात करने के लिए नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संधारण कार्य नहीं करने पर निर्धारितों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। दरिमा-मैनपाट मार्ग पर रिटेनिंग वाल, पुल-पुलियों और गार्डवाल में पेंटिंग कराने को भी कहा। सोनतराई-मैनपाट मार्ग के निरीक्षण में कमलेश्वरपुर थाना चौक से कैंप नंबर-2 मंदिर तक 1.20 किलोमीटर लंबाई में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए हटाने को कहा। भवन में टाटा वायरॉन फेंसिंग का काम कराने को भी कहा गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन के निर्माण की धीमी प्रगति पर सचिव ने नामांकित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गुणवत्ता और नियमित निगरानी के लिए अनुभवी अभिय कार्यपालन अभियताओं को भी नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए।



कमलेश्वरपुर कॉलेज को डेडलाइन, मेडिकल कॉलेज को नोटिस

कमलेश्वरपुर में टीकाकरण कॉलेज भवन के निरीक्षण में सचिव ने 15 दिसंबर तक भूतल के 50 प्रतिशत कार्डियो की ढीठई और 15 जनवरी 2027 तक भूतल का पूरा कार्डियो निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। कॉलेज के लिए चिन्हांकित भूमि का सीमांकन कराने और अवैध कब्जा मिलने पर कलेक्टर से समन्वय कर प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। सड़क संधारण की नियमित निगरानी और समय पर मरम्मत के निर्देश दिए।

दरिमा एयरपोर्ट पर री-कारपेटिंग, बाउंड्रीवाल का प्रस्ताव

दरिमा एयरपोर्ट के निरीक्षण में टर्मिनल भवन के सामने सड़क पर री-कारपेटिंग कराने और एयरपोर्ट किनारे बीसीएएस मानकों के अनुरूप बाउंड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव भेजने को कहा गया। परिसर में घास कटाई तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

कार्यालय परिसर की सफाई पर जोर

लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय भवन और सड़क परिसर का भी निरीक्षण किया गया। कार्यालय और छत की साफ-सफाई, परिसर से घास-फूस हटाने और विभागीय पौधों के रखरखाव के निर्देश दिए गए। कार्यालय परिसर में बाउंड्रीवाल, शेड निर्माण, क्वार्टरों की मरम्मत और जल निकासी के लिए प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया। दरवाजे-खिड़कियों की मरम्मत सहित अन्य कार्यों के लिए अपनाने लेकर तुरंत काम शुरू करने को कहा गया। दो दिवसीय दौरे में सचिव ने साफ कहा कि निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। हर काम तय मानकों के अनुरूप और तय समय में पूरा होना चाहिए। सड़कों की मरम्मत में देरी नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार मिलने पर जिम्मेदारियों पर कार्रवाई होगी।

6 जिलों में 32 अपराधियों पर चौथे दिन भी आईटी रेड जारी, 120 अधिकारी और 80 जवान लगे जांच में

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। पीआरए ग्रुप, बारबरीक ग्रुप, रायगढ़ स्टील और जेपी मित्तल से जुड़े अपराधियों पर आयकर की रेड चौथे दिन भी जारी रही। 18 नवंबर से अब तक 6 जिलों में 32 से ज्यादा अपराधियों पर जांच हो चुकी है। जांच में करीब 15 करोड़ कैश, 25 लॉकरों से करीब 20 करोड़ की ज्वेलरी मिलने की खबर है। बारबरीक प्रवर्तन के करीब 225 करोड़ के लेन-देन भी जांच के दायरे में हैं।

जांच टीम में 120 आयकर अधिकारी

रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सरगुजा और सूरजपुर में कार्रवाई की निगरानी भोपाल की केंद्रीय टीम कर रही है। 120 अधिकारी सीआरपीएफ के 80 जवानों की सुरक्षा में जांच कर रहे हैं। विभाग ने अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है।

कारोबार की कई कंदियां खंगाल रही टीमें

ये समूह सड़क, भवन, पुल निर्माण, स्टील, सरिया, स्पंज आयरन और जुटाने के कारोबार से जुड़े हैं। बारबरीक और रायगढ़ स्टील का कारोबार एक ही परिवार से जुड़ा है, जिसमें छह भाई अलग-अलग कंपनियां संभालते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और ओडिशा में भी इन्हें सरकारी ठेके मिले हैं। टीमें लेन-देन, बिल, बैंक गुट और



घोषित कमाई का मिलान कर रही हैं।

शेयर में निवेश और आईपीओ की तैयारी भी जांच में

रायगढ़ स्टील लिमिटेड के नतीजों में निवेश और आईपीओ लाने की तैयारी से जुड़े पहलुओं की भी जांच हो रही है।

डिजिटल सबूतों से खुलेगा लेन-देन का नेटवर्क

जब्त लैपटॉप, पेन ड्राइव और डिजिटल डिवाइस से कंपनियों के बीच लेन-देन और बैंक गुट का पता लगाया जा रहा है। कागजों और असल लेन-देन का मिलान किया जा रहा है।

रायगढ़ में तीन दफ्तरों में भी जांच

द्विमरापुर के कृष्णा कॉम्प्लेक्स के तीन कमरों में टीम पहुंची, जिसमें मुड़ता होल्डिंग भी शामिल है। कोतरारोड स्थित बैरबरीक विला में बजरंग और श्रवण अग्रवाल के घर-दफ्तर और कालिंदीकुंज मवेशियों पर भी जांच हुई।

अंबिकापुर से सूरजपुर तक कार्रवाई

अंबिकापुर में रमेशचंद्र अग्रवाल के आवास हरसिंगार, ब्रह्म रोड स्थित बैरबरीक प्रोजेक्ट्स कार्यालय और एक टैक्स वकील के घर पर पड़तील हुई। सूरजपुर निवास पर भी टीम पहुंची। यहां कच्चे कर्जदार की बहियां जब्त होने की जानकारी है।

सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए 2 दिसम्बर तक करें आवेदन



बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE -2027) 31 जनवरी 2027 को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 दिसम्बर 2026 की रात 11:50 बजे तक è https://e&ams.nta.nic.in/sainik-school-society पर किए जा सकते हैं। 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 6 दिसम्बर तक भी आवेदन किए जा सकेंगे।

रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सैनिक स्कूल है। अधिक जानकारी के लिए www.sainikschoolambikapur.org.in देखें या एनटीए हेल्पडेस्क 011-40759000 पर संपर्क करें।

फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर दें सूचना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा नियमानुसार लाभ

★ चक्रवाती तूफान अकवान से फसलों को नुकसान की आशंका, किसानों की सुरक्षा और सहायता के लिए कृषि विभाग ने जारी की महत्वपूर्ण सलाह

★ कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज कराएं शिकायत, बीमा कंपनी द्वारा 10 दिनों के भीतर कराया जाएगा सर्वेक्षण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से जिले में हुई असामयिक वर्षा और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी खड़ी एवं कटाई के बाद खेतों तथा खलिहानों में रखी धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। साथ ही चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दें, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार बीमा दावा राशि का लाभ मिल सके। कृषि विभाग द्वारा जारी सलाह में बताया गया है कि चक्रवाती तूफान अकवान के कारण जिले में असामयिक वर्षा हुई है। इससे विशेष रूप से धान की कटाई कर चुके किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। खेतों और खलिहानों में रखी धान की फसल के बारिश में भीगने तथा अधिक नमी के कारण खराब होने की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि समय रहते फसल की सुरक्षा के उपाय अपनाएं और नुकसान होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

फसल नुकसान की सूचना देने के लिए 72 घंटे की समय-सीमा महत्वपूर्ण

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल क्षति की सूचना निर्धारित समय-सीमा में देना अत्यंत आवश्यक है। जिन किसानों की बीमित फसल को चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा से नुकसान पहुंचा है, वे नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर इसकी सूचना दर्ज कराएं।

समय पर सूचना प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 10 दिनों के भीतर प्रभावित फसल का सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान फसल की वास्तविक स्थिति, नुकसान की प्रकृति और क्षति का आकलन कर संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसके आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र किसानों के बीमा दावों का निराकरण किया जा सकेगा।

कटाई के बाद खेतों में रखी धान की फसल के लिए भी बीमा प्रावधान

कृषि विभाग ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कटाई के बाद खेतों में सुखाने के लिए रखी गई बीमित धान की फसल, जिसे स्थानीय भाषा में करपा कहा जाता है, के लिए भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा का प्रावधान है। यह प्रावधान फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक लागू होता है। इस अवधि में निर्धारित जोखिमों के कारण फसल को नुकसान होने पर किसान निर्धारित समय-सीमा में सूचना देकर बीमा दावा प्रस्तुत कर



सकते हैं। विभाग ने किसानों से कहा है कि वे कटाई के बाद खेतों में रखी धान की फसल की विशेष निगरानी करें तथा मौसम की स्थिति को देखते हुए उसे सुरक्षित रखने के समुचित प्रबंध करें।

खड़ी फसल में जलभराव होने पर निर्धारित प्रक्रिया से होगा नुकसान का आकलन

कृषि विभाग के अनुसार वर्तमान में खेतों में खड़ी फसल पर जलभराव की स्थिति निर्मित होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल क्षति का आकलन किया जाएगा। ऐसे मामलों में योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज संबंधी आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा भुगतान की गणना की जाएगी। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने खेतों की स्थिति पर लगातार नजर रखें। खेतों में अत्यधिक पानी भरने की स्थिति में जहां संभव हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, ताकि फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

बीमा संबंधी सूचना देते समय आवश्यक दस्तावेज और जानकारी रखें तैयार

कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराते समय आवश्यक जानकारी उपलब्ध रखने की सलाह दी है। इनमें किसान का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम, तहसील एवं जिले का नाम, संबंधित खेत का खसरा नंबर, बीमित फसल का नाम, बीमा पॉलिसी नंबर तथा फसल को हुए नुकसान का विवरण और नुकसान की तारीख शामिल हैं।

इन जानकारियों के उपलब्ध रहने से बीमा कंपनी को शिकायत दर्ज करने और आगे की जांच एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे बीमा संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखें और शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राप्त संदर्भ संख्या भी संभालकर रखें।

राजस्व विभाग के मैदानी अमले और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी तत्काल दें जानकारी

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि चक्रवाती तूफान के कारण फसल को अधिक नुकसान होने की स्थिति में वे तत्काल राजस्व विभाग के मैदानी अमले तथा कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी इसकी जानकारी दें। इसके साथ ही प्रभावित किसान अपनी खड़ी अथवा कटाई के बाद खेतों में रखी फसल की तस्वीरें और वीडियो बनाकर सुरक्षित रखें। इन तस्वीरों और वीडियो में फसल की वास्तविक स्थिति तथा नुकसान का स्पष्ट विवरण दिखाई देना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर क्षति के आकलन में सहायता मिल सके।

खलिहानों में रखी धान की फसल को पॉलिथीन से ढककर सुरक्षित रखने की सलाह

असामयिक वर्षा को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को खेतों और खलिहानों में रखी धान की फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है। किसानों से कहा गया है कि वे धान के करपा और खलिहानों में रखी उपज को पॉलिथीन अथवा तिरपाल से अच्छी तरह ढककर रखें, ताकि बारिश के पानी से फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। जहां संभव हो, फसल को ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा उसके आसपास पानी जमा न होने दें। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में थोड़ी सी सावधानी भी किसानों की मेहनत और उपज को बड़े नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

समय पर सूचना देकर बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करें किसान

कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा के कारण फसल को हुए नुकसान की जानकारी देने में किसी प्रकार की देरी न करें। विशेष रूप से कटाई के बाद खेतों में रखी बीमित फसल को नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर निर्धारित माध्यम से सूचना दर्ज कराना आवश्यक है। समय-सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित बीमा दावे की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

विभाग ने कहा है कि किसानों की मेहनत से तैयार फसल की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान मौसम की परिस्थितियों के प्रति सजग रहें, कृषि विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करें तथा फसल क्षति की स्थिति में तत्काल संबंधित अधिकारियों और बीमा कंपनी को सूचित करें, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता मिल सके।

धनवार बैरियर पर उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा 120 क्विंटल अवैध धान जप्त, वाहन थाना बसंतपुर के सुपुर्द

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। अन्य राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में वाड्रफनगर विकासखंड के धनवार बैरियर पर उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा 120 क्विंटल (285 बोरी) धान जप्त किया गया। वाहन क्रमांक छ॥ 03 ञ -8356 में लदे इस धान के वैध दस्तावेज चालक प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद धान और वाहन दोनों जप्त कर लिए गए। यह कार्रवाई तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक की उपस्थिति में की गई। जप्त वाहन थाना प्रभारी बसंतपुर को सौंप दिया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ केवल जिले के वास्तविक किसानों को मिले, इसके लिए प्रशासन सख्त है। सीमावर्ती मार्गों पर बने



चेकपोस्ट पर तैनात अधिकारी लगातार निगरानी और रात्रि गश्त कर रहे हैं।

अन्य राज्यों से धान लाकर खरीदी केंद्रों में खपाना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत कारावास, जुर्माना और जप्ती का प्रावधान है। अवैध परिवहन में लगे ट्रक या ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे वाहनों को पुलिस जप्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 20 के तहत मंडी समिति के सचिव और अन्य लोक सेवकों को निरीक्षण, जप्ती और वाहन जप्त करने का अधिकार है। धारा 23 के तहत वे वाहनों को रोककर जाँच भी कर सकते हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अवैध धान परिवहन या बिक्री की जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी राजस्व, खाद्य या पुलिस अधिकारी को सूचना दें।

लक्ष्य 20 का, नन्हे विद्यार्थी सुना रहे 30 तक पहाड़ा, शंकरगढ़ की प्राथमिक शाला लोधी में दिखा मिशन आचार्य का असर

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 20 तक पहाड़ा याद करने का लक्ष्य तय है। लेकिन शंकरगढ़ विकासखंड की प्राथमिक शाला लोधी के विद्यार्थी इससे कहीं आगे निकल गए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री इस्माइल खान के शाला निरीक्षण के दौरान कक्षा 4 की साक्षी, शांति, आर्या और आर्यन ने 28 का पहाड़ा सुनाया। कक्षा 5 की आकांक्षा, अंशु और संजना ने 30 तक पहाड़ा सुनाकर सबको चकित कर दिया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को शाबाशी दी और शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी उत्साह बढ़ाया। यह उपलब्धि कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी की पहल पर जिले भर में चलाए जा रहे मिशन आचार्य अभियान का परिणाम है। अभियान के तहत कक्षा 5 तक के बच्चों को 20 तक और कक्षा 8 तक के बच्चों को 25 तक पहाड़ा याद कराया जा रहा है। विज्ञान और गणित कॉर्नर बनाकर गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जा रहा है, और बच्चे हर दिन रचनात्मक लेखन भी कर रहे हैं। अभियान का एक अहम हिस्सा पढ़ने की आदत विकसित करना है। विद्यालयों में रीडिंग कॉर्नर बनाए गए हैं, जहाँ बच्चों को रोचक और उम्र के अनुरूप किताबें आसानी से मिल जाती हैं। बलरामपुर पढ़ेगा हर दिन 20 मिनट के तहत बच्चे रोज 20 मिनट नियमित पुस्तक वाचन करते हैं, और अभिभावकों को भी बच्चों के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस आदत का असर बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर साफ दिखने लगा है। बच्चे अब धाराप्रवाह पढ़ने लगे हैं, पढ़ी हुई बात को समझकर अपने शब्दों में बताने लगे हैं, और उनकी शब्दावली भी समृद्ध हो रही है। पढ़ने में बढ़ी रुचि ने उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया है, जिसका लाभ दूसरे विषयों की पढ़ाई में भी मिल रहा है।



अभियान से बच्चों के पठन और लेखन कौशल, रचनात्मकता और गणितीय संक्रियाओं की समझ में लगातार सुधार हो रहा है। शिक्षकों में भी नई ऊर्जा आई है, और वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के ज्ञान और कौशल को निखारने में जुटे हैं। जिले के सभी विद्यालयों में ये गतिविधियाँ नियमित रूप से कराई जा रही हैं, जिससे पूरे जिले का शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो रहा है।

वीबी जी रामजी योजना की समीक्षा, शंकरगढ़ में 1 दिसंबर से 8 हजार श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सभाकक्ष में वीबी जी रामजी योजना की समीक्षा बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वेदप्रकाश पाण्डेय और कार्यक्रम अधिकारी ने ग्राम पंचायतवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और मैदानी अमले को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, सरपंच, मेट, ग्राम रोजगार सहायक सहित जनपद के संबंधित अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

बैठक में बताया गया कि आगामी 01 दिसंबर से 8,000 श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में पर्याप्त कार्य उपलब्ध रखने की कार्ययोजना समय रहते तैयार करने के निर्देश दिए गए। हर ग्राम पंचायत को 10 श्रम आधारित कार्यों की फाइल आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो दिन के भीतर जनपद कार्यालय में जमा करनी होगी। युक्तधारा-वीजीपीपी पोर्टल पर हर पंचायत को कम से कम एक कार्य की प्रविष्टि सुनिश्चित करनी होगी। जल संचय जन भागीदारी पोर्टल पर पूर्ण कार्यों और सुग्घर बाड़ी की ऑनलाइन प्रविष्टि भी लक्ष्य के अनुरूप समय पर दर्ज करने को कहा गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण और निर्माणाधीन आवासों की समीक्षा कर लंबित आवास जल्द पूरे कराने पर विशेष जोर दिया गया। ई-केवायसी और जल दूत अभियान के शेष कार्य प्राथमिकता से पूरे कर शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशिक्षण सत्र में विकसित ग्राम पंचायत योजना, सुग्घर बाड़ी और जल संचय जन भागीदारी पोर्टल की कार्यप्रणाली और ऑनलाइन प्रविष्टि के चरणों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, ताकि पंचायत स्तर पर पोर्टल समय पर अद्यतन हो सकें।

अंत में जनपद सीईओ श्री पाण्डेय ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को आपसी समन्वय और टीम भावना से काम करते हुए लक्ष्य समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी अमले से योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा जताई।

औचक निरीक्षण पर निकले जिला शिक्षा अधिकारी, 14 विद्यालयों की परखी व्यवस्था, लापरवाही पर दो संकुल समन्वयक को नोटिस

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एन.के. निरापुरे ने शनिवार सुबह विद्यालयीन समय में जिले के 14 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा परिसर की स्वच्छता का जायजा लिया। कक्षाओं में पहुँचकर उन्होंने खुद विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनकी शैक्षणिक समझ परखी। उपस्थिति पंजी और दैनंदिनी की जाँच कर सभी शिक्षकों को दैनंदिनी का नियमित संधारण करने के निर्देश दिए।

प्राथमिक और माध्यमिक शाला लुर्गीकला में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम मिलने पर उन्होंने प्रधान पाठक सनू राम सूर्यवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। विद्यालयों में रंगाई-पोताई और साफ-सफाई की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने एक सप्ताह में व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी अपने विकासखंड के सभी विद्यालयों में रंगाई-पोताई और स्वच्छता सुनिश्चित कराने को कहा गया। हायर सेकेंडरी विद्यालय रनहट और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चलगली में उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की। शिक्षकों को समय-सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा कराने और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार कराने के निर्देश दिए।



सतपता में सूने मकान में अज्ञात चोरों ने सोने-चांदी के आभूषण किया पार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत सतपता में एक घर से अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर ली है। बिश्रामपुर पुलिस ने बताया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत सतपता निवासी प्रेमदान अर्पण कुजूर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि वे अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। मंगलवार की रात करीब 10 बजे घर लौटने पर मुख्य गेट खुला मिला। अंदर घुसते ही देखा कि पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा है और कमरे में रखी आलमारी का ताला तोड़ दिया गया है। आलमारी से सोने की एक चेन, सोने की दो नग बाली, सोने के दो टॉप्स, चांदी की एक जोड़ी पायल, सोने की दो नग अंगूठी गायब पाए गए। चोरी गए आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग 70 हजार रुपए बताई गई है। प्रार्थी ने घटना की सूचना थाना में दी है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के दो वर्ष बाद भी चांदनी बिहारपुर में आज तक नहीं खुली सहकारी बैंक शाखा

40 गांवों के किसान परेशान, बैंकिंग कार्य हेतु 60 से 80 किमी दूर ओड़गी जाने को मजबूर अन्नदाता

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिहारपुर। सूरजपुर जिले के दूरस्थ एवं पहाड़ी अंचल चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने की मुख्यमंत्री की घोषणा आज तक पूरी नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 1 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम के दौरान बिहारपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की थी। इस घोषणा से क्षेत्र के हजारों किसानों में उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें बैंकिंग कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन करीब दो वर्ष बीतने के बाद भी बैंक शाखा शुरू नहीं हो सकी है। विडंबना यह है कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बिहारपुर क्षेत्र के किसानों को आज भी बैंकिंग कार्यों के लिए 60 से 80 किलोमीटर दूर ओड़गी जाना पड़ रहा है। धान बिक्री की राशि निकालने, किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण नवीनीकरण, खाता संचालन सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए किसानों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों जगह भाजपा की सरकार है। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी भाजपा के जनप्रतिनिधियों के हाथों में है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की घोषणा के लगभग दो वर्ष बाद भी बिहारपुर में सहकारी बैंक शाखा नहीं खुलना समझ से परे है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं बैंक शाखा खोलने की घोषणा कर चुके हैं, तो संबंधित विभाग अब तक आवश्यक कार्रवाई पूरी क्यों नहीं कर पाया।

धान खरीदी के बीच किसानों की बढ़ी परेशानी

क्षेत्र में नवगई एवं मोहरसोप धान खरीदी केंद्र संचालित हैं, जहां आसपास के गांवों के हजारों किसान अपनी उपज बेचने पहुंच रहे हैं। धान खरीदी के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को बैंकिंग सुविधाओं की सबसे अधिक जरूरत होती है। स्थानीय स्तर पर बैंक शाखा नहीं होने से किसानों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी ओड़गी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। चांदनी बिहारपुर क्षेत्र भौगोलिक रूप से दुर्गम और पहाड़ी इलाका है। यहां के कई गांवों से ओड़गी



पहुंचना आसान नहीं है। किसानों को बस बदलकर या निजी वाहनों के सहारे बैंक जाना पड़ता है। आने-जाने में 300 से 1000 रुपये तक खर्च होने के साथ पूरा दिन भी बर्बाद हो जाता है। कई बार बैंक पहुंचने के बाद लंबी कतार या अन्य कारणों से काम नहीं होने पर किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है।

40 गांवों के हजारों किसान प्रभावित

बिहारपुर क्षेत्र के महुली, कोल्हुआ, खोहीर, कछवारी, जुड़वनिया, रामगढ़, बैजनपाठ, लुल्ह, भुंडा, तेलाईपाठ, रसौकी, उमझर, चौगा, करौटी, खैरा, कठिया, बसनारा, मोहरसोप, ठाड़पाथर, पेंडारी, बेगारीडाड़, अंतिकापुर, नवाटोला, सपहा, कुबेरपुर, खालपारा, उमापुर, पासल सहित लगभग 40 गांवों के हजारों ग्रामीण इस समस्या से प्रभावित हैं। क्षेत्र की अधिकांश आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। ऐसे में सहकारी बैंक की स्थानीय सुविधा नहीं होना किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है।

मंत्री और सांसद के समक्ष भी उठा चुके हैं मांग

ग्रामीणों द्वारा कई बार क्षेत्रीय विधायक एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के समक्ष बिहारपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा खोलने की मांग रखी जा चुकी है। वहीं सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज से भी ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान की मांग की है। इसके बावजूद अब तक बैंक शाखा स्थापना को लेकर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। क्षेत्र के किसानों एवं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सहकारिता विभाग, जिला प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज तथा सूरजपुर कलेक्टर से मांग की है कि किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए बिहारपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा तत्काल खोली जाए। किसानों का कहना है कि अब केवल घोषणा और आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि बैंक भवन, कर्मचारियों की नियुक्ति एवं शाखा संचालन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।

ताकि क्षेत्र के लगभग 40 गांवों के किसानों को 60 से 80 किलोमीटर दूर ओड़गी जाने की मजबूरी से राहत मिल सके।

26 नवंबर को आयोजित होगा मुख्यमंत्री जनदर्शन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन कार्यक्रम 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री आम नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं, मांगें और सुझाव सुनेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन में किया जाएगा। जनदर्शन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।

तीन घंटे तक आमजनों से करेंगे मुलाकात

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे से जनदर्शन की शुरूआत होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नागरिकों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुनेंगे। जनदर्शन में आने वाले लोगों को अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों और शासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने में सुविधा मिल सके।

समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को देंगे निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन के दौरान नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर



संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। वे समस्याओं के त्वरित एवं यथोचित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। जनदर्शन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर पहुंचने वाले नागरिक अपनी शिकायतों से मुख्यमंत्री को अवगत करा सकेंगे। इसके बाद संबंधित मामलों को उनके विभागीय स्तर पर निराकरण के लिए भेजने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

आम नागरिकों को मिलेगा सीधे बात रखने का अवसर

मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम आम लोगों के लिए अपनी समस्याएं सीधे सरकार के सामने रखने का एक माध्यम है। इसमें नागरिक अपनी मांगों, शिकायतों और सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री उनकी बात सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देंगे।

मुख्यमंत्री से मिला कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नया रायपुर स्थित निवास कार्यालय में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न सामाजिक प्रमुखों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। समारोह में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने भी शिरकत की। समाज के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा एवं सचिव राजेश दीक्षित, अनुराग पांडे, अजय अवस्थी ने समाज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री विष्णु



देव साय से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने भी समाज के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ सदस्यों का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें दीपोत्सव की बधाई दी। इस दौरान प्रदेश के सामाजिक समरसता और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा भी हुई।

विश्व मात्स्यिकी दिवस पर संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित, 400 मत्स्य कृषकों ने लिया हिस्सा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। विश्व मात्स्यिकी दिवस 2026 के अवसर पर आज ऑडिटोरियम, पी.जी. कॉलेज अंबिकापुर में संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संभाग के सभी जिलों से लगभग 400 मत्स्य कृषकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सरगुजा के उपाध्यक्ष देवनारायण यादव उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की सभापति श्रीमती दिव्या सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनिमा केरकेट्टा एवं श्रीमती नानमणि पैंकरा सहित मछुआ समाज के प्रतिनिधि, संभाग



के विभिन्न जिलों के अधिकारी एवं मत्स्य निरीक्षक उपस्थित रहे।

आधुनिक तकनीकों और स्वरोजगार की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान मत्स्य कृषकों को मछली पालन की आधुनिक तकनीकों एवं स्वरोजगार की संभावनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान झींगा पालन, तिलापिया पालन, एनएफडीपी (एनएफडीपी) पोंटल में मत्स्य कृषकों का पंजीयन तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने मत्स्य कृषकों को योजनाओं का लाभ लेने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने तथा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

जाल, आइस बॉक्स और प्रमाण पत्र का वितरण

इस अवसर पर मत्स्य कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप जाल, आइस बॉक्स एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में संभाग के विभिन्न जिलों से आए मत्स्य कृषकों ने योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा की।

बढ़ती आबादी, बढ़ते आयोजन, जगह एक ही, रामानुजगंज को चाहिए नया मैदान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रमुख शहर रामानुजगंज में बड़े राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक बड़े मैदान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। शहर की बढ़ती आबादी और सालभर होने वाले विभिन्न आयोजनों के बावजूद यहां बड़े सार्वजनिक मैदान के रूप में मुख्य रूप से हाईस्कूल मैदान ही उपलब्ध है। ऐसे में आयोजनों के दौरान आयोजकों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि कुछ दशक पहले तक रामानुजगंज की आबादी मुख्य रूप से मध्य बाजार



एवं उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन बीते दो दशकों में शहर का तेजी से विस्तार हुआ है। आज रामानुजगंज की आबादी 25 हजार से अधिक हो चुकी है। शहर के विभिन्न वार्डों में आवासीय बस्तियों का विस्तार होने के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है।

रामानुजगंज में वर्षभर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। राजनीतिक सभाएं, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक महोत्सव, खेलकूद प्रतियोगिताएं, मेले और सार्वजनिक समारोहों के लिए बड़े एवं खुले स्थान की जरूरत पड़ती है। लेकिन पर्याप्त मैदान नहीं होने के कारण इन सभी आयोजनों का दबाव एकमात्र हाईस्कूल मैदान पर ही रहता है। कई बार एक ही मैदान में लगातार आयोजन होने से व्यवस्थाओं और आम लोगों की सुविधाओं को लेकर भी परेशानी खड़ी होती है। शहर की वर्तमान आबादी और भविष्य में होने वाले विस्तार को देखते हुए एक अतिरिक्त बड़े सार्वजनिक मैदान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यदि शहर में उपयुक्त स्थान पर एक व्यवस्थित मैदान विकसित किया जाए तो वहां बड़े आयोजनों के साथ खेलकूद गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही हाईस्कूल मैदान पर आयोजनों का दबाव कम होगा और विद्यार्थियों को भी अपने विद्यालय के मैदान का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा। शहर के विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है। ऐसे में रामानुजगंज में दूसरे बड़े सार्वजनिक मैदान के निर्माण की मांग और आवश्यकता को लेकर नगरीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पहल किए जाने की जरूरत है।

प्रीमियम शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी, 5 हजार तक सस्ता हुआ जॉनी वॉकर 18 ईयर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किए जाने के बाद कई प्रीमियम विदेशी शराब ब्रांडों की कीमतों में कमी आई है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए 33 विदेशी शराब ब्रांडों की संशोधित दरों को मंजूरी दी है। नई सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे चर्चित ब्रांड शामिल हैं। नई दरों के मुताबिक, जॉनी



वॉकर 18 ईयर के एक केस की कीमत में करीब 5 हजार रुपये की कमी आई है। वहीं, सिंगलटन 12 ईयर के एक केस पर 2,817 रुपये तक की राहत मिली है। जॉनी वॉकर ब्लू लेबल के एक केस की लैंडिंग कीमत 92,939 रुपये और रॉयल सैल्यूट 21 ईयर की 64,079 रुपये निर्धारित की गई है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के तहत दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में आयात-निर्यात शुल्क कम करने का प्रावधान है। इसका लाभ अब विदेशी शराब के कारोबार में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि, सरकारी शराब दुकानों में ग्राहकों को वास्तविक रूप से कितनी कीमत कम चुकानी होगी, यह राज्य सरकार की खुदरा मूल्य निर्धारण नीति पर निर्भर करेगा।

28 नवंबर को होगा आईएसईआई ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, 6 श्रेणियों में मिलेगा सम्मान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स (इंडिया) के द्वारा 28 नवंबर को रायपुर के होटल ग्रैंड इम्पेरिया में 'आईएसईआई ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड' का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों, पेशेवरों, संगठनों और संस्थानों को सम्मानित करना है संस्था के सह निदेशक डॉ. एम.एस. नवाज ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सुरक्षा, पर्यावरण और आपदा



प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवरों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 'ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड' पहल के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना, पेशेवर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और दुर्घटनाओं की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण तथा आपदाओं में होने वाले नुकसान को कम करना है।

छह प्रमुख श्रेणियों में मिलेगा सम्मान

यह पुरस्कार समारोह छह प्रमुख श्रेणियों में किए गए बेहतरीन कार्यों और उपलब्धियों को मान्यता देगा - सुरक्षा और स्वास्थ्यपर्यावरण और स्थिरता, आपदा प्रबंधनगुणवत्ता और ईएचएसक्यू, नेतृत्व और नवाचार, अनुसंधान और नवाचार,

मुख्य थीम - सुरक्षित समुदाय, हरित पर्यावरण

इस कार्यक्रम की मुख्य थीम, हदुर्घटना रोकथाम की ओर हरित पर्यावरण' सुरक्षित समुदाय, सुरक्षा प्रथाओं को मजबूत करने, पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने, आपदा जोखिमों को कम करने और आपदाओं का सामना करने में सक्षम समुदायों के निर्माण के महत्व को दर्शाती है। इस पहल का लक्ष्य उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों में एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। यह व्यावसायिक सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पेशेवर दक्षता, तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और नेतृत्व के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करता है। यह कार्यक्रम बेहतरीन पहलों को मान्यता देने, पेशेवर अनुभवों को साझा करने और सुरक्षित कार्यस्थलों तथा स्थिर समुदायों के निर्माण के लिए नए दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।

चिंतन

कर्मचारियों को राहत देने वाला फैसला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) की जमा राशि किस्तों में निकालने की योजना को मंजूरी देकर एक राहत वाला फैसला दिया है। बीमारी, बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या मकान खरीदने जैसी जिम्मेदारियों के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए पीएफ की रकम बड़ा सहारा बन सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने निकासी के नियमों में बदलाव कर कर्मचारियों को इसी जरूरत के अनुरूप राहत देने की पहल की है। नौकरी के दौरान पीएफ से निकासी की सीमा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना और निकासी के लिए एक साल की नौकरी की अनिवार्यता समाप्त कर केवल दो महीने की सदस्यता के बाद बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकालने की सुविधा देना स्वागत योग्य कदम है। दरअसल, पीएफ कर्मचारी की अपनी मेहनत की कमाई है। इसमें कर्मचारी के साथ नियोक्ता का भी योगदान होता है। ऐसे में जरूरत के समय अपनी जमा पूंजी का उपयोग करने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना कई बार परेशानी को बढ़ा देता है। नए नियमों से कर्मचारियों को नौकरी छूटने जैसी अप्रत्याशित परिस्थिति में आर्थिक संकट से उबरने के लिए अपेक्षाकृत जल्दी अपनी बचत का सहारा मिल सकेगा। इससे उसे महंगे ब्याज पर कर्ज लेने या दूसरों के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी से भी बचाया जा सकता है। निकासी की सीमा 90 प्रतिशत करने के साथ खाते में 10 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखने का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। इससे कर्मचारियों को वर्तमान की जरूरतों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा और भविष्य की सुरक्षा का न्यूनतम आधार भी बना रहेगा। नियमों को सरल बनाने और ऑनलाइन दावों की प्रक्रिया को सुगम करने का उद्देश्य भी सराहनीय है। सामाजिक सुरक्षा की किसी व्यवस्था की सार्थकता इसी में है कि जरूरत के समय उसका लाभ बिना अनावश्यक कागजी औपचारिकताओं और देरी के मिल सके। ईपीएफओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों में बदलाव का लाभ वास्तव में कर्मचारियों तक पहुंचे और दावों के निपटान में पारदर्शिता तथा समयबद्धता बनी रहे। हालांकि, इस राहत के साथ कर्मचारियों को अपनी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा के प्रति भी सचेत रहना होगा। पीएफ में जमा राशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज वर्षों में बड़ी पूंजी तैयार करता है और यह बुढ़ापे का सहारा बनता है। समय से पहले बड़ी रकम निकालने से इस वृद्धि पर असर पड़ता है और सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध राशि घट सकती है। इसलिए अधिक निकासी की सुविधा को अनावश्यक खर्चों का माध्यम बनाने के बजाय वास्तविक जरूरतों तक सीमित रखना चाहिए। खासकर नौकरी छूटने की स्थिति में नई नौकरी मिलने तक खर्चों का प्रबंधन करते हुए पीएफ की बचत का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है। कर्मचारी हित में किए गए ऐसे बदलाव तभी पूरी तरह सफल होंगे, जब सुविधा के साथ जागरूकता भी बढ़े। ईपीएफओ को कर्मचारियों को निकासी की शर्तों, पात्रता और भविष्य की बचत पर पड़ने वाले प्रभावों की स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। पीएफ केवल एक बचत खाता नहीं, बल्कि करोड़ों नौकरीपेशा परिवारों के भविष्य का सुरक्षा कवच है। इसे जरूरत के समय इस्तेमाल करने की सुविधा देना निश्चित रूप से राहतकारी फैसला है। आखिरकार सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य केवल भविष्य के लिए धन जमा करना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में कर्मचारी और उसके परिवार के काम आना भी है।



मुद्दा
कांतिलाल मांडोत

कमियां ही न गिनाएं, समाधान भी सुझाएं

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और सत्ता को जवाबदेह बनाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन विपक्ष की राजनीति केवल आलोचना और आरोपों तक सीमित रह जाए तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगते हैं। देश को केवल यह बताने से काम नहीं चलेगा कि समस्याएं कितनी हैं, बल्कि यह भी बताना होगा कि उनका समाधान कैसे होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारत में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश के युवाओं को भविष्य की चिंता सता रही है और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं। इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी और चुनावी निष्पक्षता लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की समस्याओं को विदेश में गिनाने से उनका समाधान निकल आएगा? क्या राहुल गांधी के पास इन समस्याओं को दूर करने की कोई ठोस योजना भी है?

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, और सत्ता को जवाबदेह बनाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन विपक्ष की राजनीति केवल आलोचना और आरोपों तक सीमित रह जाए तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगते हैं। केवल यह बताने से काम नहीं चलेगा कि समस्याएं कितनी हैं, बल्कि यह भी बताना होगा कि उनका समाधान कैसे होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वे इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारत में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं।

पिछले ग्यारह वर्षों में राहुल गांधी कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अलग-अलग अवसरों पर उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में किसी भी नेता को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता विदेश में भारत की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाता है तो उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह देश की उपलब्धियों और संभावनाओं को भी सामने रखे। भारत केवल समस्याओं से घिरा देश नहीं है। यहां विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, सड़क, रेल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। भारतीय युवा दुनिया के अनेक देशों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। इन उपलब्धियों को स्वीकार करना किसी सरकार का समर्थन करना नहीं, बल्कि देश की प्रगति को पहचानना है। राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस के पास इसका क्या समाधान है। युवाओं को रोजगार चाहिए, केवल भाषण नहीं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है। सरकार से रोजगार के आंकड़ों और रिक्त पदों पर सवाल पूछना उचित है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी रोजगार नीति जनता के सामने रखनी चाहिए। कांग्रेस यह बताए कि सत्ता में आने पर वह कितने रोजगार के अवसर पैदा करेगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाएगी। केवल निराशा का वातावरण बताने से युवाओं का विश्वास नहीं जीता जा सकता। इसी तरह राहुल गांधी ने मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को हर उचित सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था

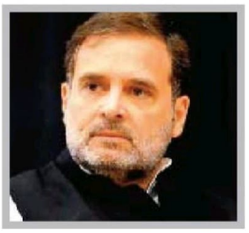

पर आरोप लगाने से पहले उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना भी जरूरी है। यदि कांग्रेस के पास मतदाता सूची में गड़बड़ी या चुनावी अनियमितता से जुड़े दस्तावेज हैं तो उन्हें निर्वाचन आयोग के सामने रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रास्ता अपनाना चाहिए। लोकतंत्र में आरोप लगाने की स्वतंत्रता के साथ प्रमाण देने की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। बिना ठोस आधार के बार-बार संदेह जताने से मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना करना राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। राजनीतिक विरोध और वैचारिक मतभेद लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और उसे उसे जनता के सामने रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन हर मुद्दे को मोदी, शाह या संघ के विरोध से जोड़ देने से जनता की मूल समस्याओं पर चर्चा कमजोर पड़ जाती है। देश की राजनीति व्यक्तियों के विरोध से आगे बढ़कर नीतियों और विकास के विकल्पों पर केंद्रित होनी चाहिए। यहां एक बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व से भी है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता आखिर चुप क्यों रहते हैं? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा मंच नहीं है जहां विदेश में दिए गए बयानों की समीक्षा हो सके? क्या पार्टी नेतृत्व यह नहीं देखता कि इस तरह के बयानों से आम मतदाता के बीच क्या संदेश जाता है? किसी भी राजनीतिक दल में नेतृत्व की बात महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। कांग्रेस को अपने नेता के हर बयान का समर्थन करने के बजाय तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन करना चाहिए। यदि किसी बयान से देश के भीतर या बाहर गलत संदेश जाता है तो उस पर स्पष्टता देना पार्टी का दायित्व है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने की है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार के अनेक आरोप और विवाद तत्कालीन सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गए थे। जनता ने चुनाव में अपना निर्णय सुनाया और सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद भी कांग्रेस अपने संगठन और राजनीतिक कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव नहीं कर पाई। केवल प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने से पार्टी का खोया जनाधार वापस नहीं आने वाला। जनता को यह जानना है कि कांग्रेस के पास देश के विकास, रोजगार, शिक्षा, किसान, मजदूर और मध्यमवर्ग के लिए कौन सी नई योजनाएं हैं। राजनीति में विरोध करना आसान है, लेकिन जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प रखना कठिन जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि मतदाता अब केवल भाषण सुनकर निर्णय नहीं करता। वह काम, नेतृत्व, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को भी देखता है। विदेश में जाकर भारत की कमियां गिनाने के बजाय उन्हें यह बताना चाहिए कि उन कमियों को दूर करने के लिए उनकी पार्टी क्या करेगी। सरकार को भी आलोचनाओं का जवाब तथ्यों और अपने काम के आधार पर देना चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है। देश की छवि किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। सरकार की गलतियों पर सवाल उठना चाहिए और विपक्ष की गलतियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लगातार आरोप लगाने से मतदाताओं का दिल नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस को भी अपने नेतृत्व से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर पार्टी देश को कौन सा रास्ता दिखाना चाहती है। जनता को आरोपों की राजनीति नहीं, समाधान की राजनीति चाहिए। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी केवल समस्याओं की सूची पेश करने के बजाय उनका व्यावहारिक समाधान बताएं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंथन
राज कुमार सिन्हा



जलवायु सम्मेलन से आगे जवाबदेही की चुनौती

तुर्की के अंतल्या में 9 से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप 31) का मुख्य ध्यान वादों को जमीनी अमल में बदलने का रहा। मेजबान तुर्की ने 2035 तक दुनिया की कुल ऊर्जा जरूरतों का 35% हिस्सा बिजली से पूरा करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटे। पिछले सम्मेलन में शुरू किए गए वन संरक्षण कोष को आगे बढ़ाने और राजनीतिक समर्थन मजबूत करने पर जोर दिया गया है। आगे के लिए हरित उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जैव विविधता, समुद्री संरक्षण, विज्ञान और युवा भागीदारी को नीतिगत क्रियान्वयन से जोड़ना आगे की प्रमुख दिशा है। सम्मेलन में भारत ने 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि को पार करने की संभावना से पैदा हो रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामूहिक प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए समानता अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपना उचित योगदान देने के साथ-साथ अपने लोगों के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने यह भी कहा कि 'न्यायसंगत बदलाव' और अनुकूलन संबंधी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर विकासशील देशों के लिए, जहां ये मुद्दे विकास की चुनौती के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। जलवायु वित्त के मामले में, भारत ने जोर दिया कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए अनुकूलन वित्त को मजबूत करने में विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के महत्व को रेखांकित किया, जो विकसित देशों के लिए यह दायित्व तय करता है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में (कोप - 21) अपनाया गया और यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे रखना और इसे 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास करना है। इस समझौते में 194 देश और यूरोपीय संघ (कुल 195 पक्षकार) शामिल हैं। 4 नवंबर 2026 को इस समझौते के लागू होने के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। यह समझौता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने, जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन बढ़ाने और विकासशील देशों को वित्तीय व तकनीकी सहायता देने पर केंद्रित है। कोप-31 के बाद सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को ठोस नीतियों और जमीनी कार्रवाई में बदलने की होगी। इसके लिए विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए विकासशील देशों को पर्याप्त, सुलभ और अतिरिक्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराना होगा। विशेष रूप से अनुकूलन, जलवायु आपदाओं से होने वाले नुकसान और क्षति तथा तकनीकी सहयोग के लिए वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। भविष्य की जलवायु रणनीति में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने, सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देने और ऊर्जा की मांग को अधिक टिकाऊ तरीके से पूरा करने पर जोर देना होगा। इसके साथ ही ऊर्जा उत्पादन और उपभोग की ऐसी नीतियां विकसित करनी होंगी, जिनसे पर्यावरणीय नुकसान, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव कम हो। जंगलों, नदियों, समुद्रों, जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण इसका अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आदिवासी, किसान, मछुआरे और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, अधिकारों और भागीदारी को जलवायु नीतियों में उचित स्थान देना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, वन संरक्षण और आजीविका सुरक्षा की योजनाओं को मजबूत करना होगा। युवाओं, महिलाओं और प्रभावित समुदायों की सक्रिय भागीदारी के बिना जलवायु कार्रवाई प्रभावी नहीं हो सकती। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय, विकास और मानव अस्तित्व से जुड़ा गंभीर वैश्विक संकट है। पृथ्वी का भविष्य केवल सरकारों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्णयों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि विकास की हमारी वर्तमान दिशा कितनी न्यायपूर्ण, टिकाऊ और प्रकृति के अनुकूल बनती है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

भीतरी पराधीनता से मुक्ति



स्वाधीनता किसे अच्छी नहीं लगती? हर किसी की चाह होती है सारे बंधनों से मुक्त होने की। पिंजरे में बंद पक्षी हो या रस्सी से बंधा हुआ पशु, हर प्राणी स्वतंत्रता या स्वाधीनता चाहता है। फिर मनुष्य, जिसकी चेतना इन पशु-पक्षियों से कहीं श्रेष्ठ है, भला वह क्यों नहीं चाहेगा स्वाधीन होना? इसीलिए हर सभ्यता में मनुष्य ने सदैव स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया है। तो



संकलित
दर्शन

क्या आज मानव जाति स्वाधीन है? शायद आप कहेंगे- हां। यह सही भी है, किंतु यदि हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि सौभाग्य से मानव जाती बाह्य स्वतंत्रता तो पा चुकी है, किंतु दुर्भाग्य से आज बहुत बड़े स्तर पर भीतरी पराधीनता से त्रस्त है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनी इस भीतरी पराधीनता को ही स्वाधीनता समझने लगे हैं, क्योंकि स्वाधीनता की हमारी सोच अत्यंत बचकानी हो गई है। पराधीनता दो प्रकार की होती है- बाहरी और भीतरी। बाहरी पराधीनता से स्वाधीन होना फिर भी आसान है, क्योंकि हमें बाहरी स्वाधीनता की प्रतीति होती है और हम पूरी जान लगाकर उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन भीतरी पराधीनता से मुक्ति..? हमें तो अपनी इस भीतरी पराधीनता की प्रतीति तक नहीं है, फिर स्वाधीनता का प्रयास कैसे होगा? हम आज भी पराधीन हैं - कई स्तरों पर, कई रूपों में। तो क्या है यह भीतरी पराधीनता? किसके अधीन हैं हम? आपने देखा होगा कि लोग बड़े गर्व से अक्सर कहते हैं, 'मुझे यह पसंद है, इसलिए मैं यह करके रहूंगा और वह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वाधीन हूं।'

बच्चे की राजा के समक्ष चार शर्तें



एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया तो रास्ते में क्या देखता है कि, एक छोटा बच्चा माटी के खिलौनो को कान में कुछ कहता फिर तोड कर माटी में मिला रहा है। राजा को बड़ा अचरज हुआ तो उसने बच्चे से पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इन से पूछता हूँ कि कभी राम नाम जपा? और माटी को माटी में



संकलित
प्रेरणा

मिला रहा हूँ। तो राजा ने सोचा इतना छोटा सा बच्चा इतनी ज्ञान की बात..राजा ने बच्चे से पूछा कि तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? तो बच्चे ने कहा कि जरुर रहूंगा पर मेरी चार शर्त है। 0 जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा। मैं भोजन खाऊंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। 0 मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। 0 और जब मैं कभी मुसीबत में होऊ तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़ कर मेरे पास आना पड़ेगा। आप यदि हमारी ये सभी शर्तें मानते हैं, तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा कि ये तो असम्भव है। तो बच्चे ने कहा राजन तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़ कर आपके आसरे क्यूँ रहूँ। जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है। खुद भूखा रह कर मुझे खिलाता है। खुद जागता है और मैं निश्चिंत सोता हूँ। और जब मैं किसी मुश्किल में होता हूँ, तो वो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़ कर दौड़ा आता है। कहने का भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विकारो में उलझ कर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं।

अंतर्मन



आज की पाती

डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ता जाल

डिजिटल क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था और नागरिक जीवन को नई गति दी है। आज मोबाइल फोन के माध्यम से पैसे भेजना, बिलों का भुगतान करना, खरीददारी करना और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट ने वित्तीय लेन-देन को आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक गंभीर चुनौती भी तेजी से उभरी है- साइबर धोखाधड़ी। तकनीक ने जहां आर्थिक गतिविधियों को सरल बनाया है, वहीं अपराधियों को लोगों की मेहनत की कमाई तक पहुंचने के नए रास्ते भी उपलब्ध कराए हैं। आज साइबर अपराध केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक विश्वास और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है। - विनोद जागलाल, हिसार

करंट अफेयर

डच चित्रकार वैन गॉग की पेंटिंग ने बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया

विंसेंट वैन गॉग की एक पेंटिंग ने इस डच चित्रकार की नीलामी के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह कृति 19.04 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारी-भरकम कीमत पर नीलाम हुई है। नीलामी घर सोदबी ने कहा कि 'चेस्टनट ट्रीज इन ब्लॉसम' नामक पेंटिंग के विक्रेता और इसके पिछले यहूदी मालिकों के बीच एक समझौते के बाद बुधवार को न्यूयॉर्क में इस रचना की बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ी। साल 1890 में प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु से पहले की अंतिम कृतियों में से एक, यह पेंटिंग नाजी जर्मनी के दौर की लूट का हिस्सा होने के विवाद में घिरी हुई थी। इस कलाकृति के मालिक ब्लाक्वियर-एरीटा परिवार ने कहा, फिशर के उत्तराधिकारियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचकर हमें खुशी हो रही है। परिवार ने आगे कहा, हम उस रचनात्मक संवाद की सराहना करते हैं जिसने इस समाधान को संभव बनाया, और हम एक असाधारण परिणाम की उम्मीद करते हैं तथा इस उत्कृष्ट कृति को संग्राहकों की नई पीढ़ी को सौंपने के लिए उत्सुक हैं। सोदबी के अनुसार, यह उस दौर की उन सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है जो अब तक निजी हाथों में सुरक्षित रही हैं।



ऑफ बीट

आम पकने के पहले ही क्यों गिर जाते हैं

ऑस्ट्रेलिया में हर मौसम में आम उत्पादकों को उस समय भारी नुकसान होता है, जब पेड़ों से बड़ी संख्या में फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि तनाव के दौरान पेड़ों में हार्मोनल असंतुलन और कार्बोहाइड्रेट की कमी पैदा हो जाती है। फल के विकास के लिए आवश्यक शर्करा की आपूर्ति बाधित होने पर पेड़ अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देता है और फल गिर जाता है। शोधकर्ताओं ने इसे एक आणविक "क्विट सिग्नल" बताया है, जो पेड़ को फल का साथ छोड़ने का संदेश देता है। यह संकेत जीन गतिविधि और हार्मोनल संकेतों के जटिल नेटवर्क से जुड़ा है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिक आम के डंठल (पेडिसल) के ऊतकों में जीन गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पेड़ और फल के बीच पोषक तत्वों और संकेतों का आदान-प्रदान होता है। फल झड़ने की समस्या के लिए शोध में पौध वृद्धि नियामकों (प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स) के उपयोग को एक प्रभावी उपाय बताया गया है। ये हार्मोन के कृत्रिम रूप होते हैं, जो तनाव की स्थिति में पेड़ों में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। परीक्षणों में पाया गया कि फूल आने के शुरुआती चरण में इनका प्रयोग अधिक प्रभावी रहा, जिससे पैदावार में 17 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई।



ट्रेंड

अर्थशॉट प्राइज



वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी से मिलकर बहुत खुशी हुई। जलवायु संबंधी अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने और वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में भारतीय सूझबूझ को प्रदर्शित करने के लिए 'अर्थशॉट प्राइज' के प्रयासों की सराहना करता हूँ। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रेम का अनुभव



डर, क्रोध और नफरत ने भाजपा और आरएसएस समर्थकों के दिलों में एक ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम को महसूस करने और उसे व्यक्त करने से रोकता है। एक सच्चे हिंदू के नाते, मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूँ, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम का अनुभव कर सकें। - राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

आत्मनिर्भरता की पहचान



यूपीआई से लेकर स्वदेशी वैक्सीन, वंदे भारत से लेकर ब्रह्मोस और तेजस तक, जिन उपलब्धियों पर कभी संदेह जताया गया, आज वही भारत की सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। - संजय भाटिया, रास सांसद, भाजपा

गंदी राजनीति



केंद्रीय कृषि मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी की है। दुर्भाग्य से, वे और उनकी पार्टी, कांग्रेस के साथ मिलकर, गंदी राजनीति के तहत दिन-रात पंजाब के किसानों को भला-बुरा कहते रहते हैं। -अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
66/1 इंडस्ट्रियल एरिया, रिछाई, जबलपुर (मप्र)
पिन कोड-482002
ई-मेल : edit@haribhoomi.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

वीजा, मास्टरकार्ड और जेपी मॉर्गन के वेंडर्स का डेटा लीक, भुगतान नेटवर्क पर असर नहीं

एजेंसी ▶▶ वॉशिंगटन

जेपी मॉर्गन, चेस, वीजा और मास्टरकार्ड ने अपने बाहरी सेवा प्रदाताओं (वेंडर्स) से जुड़े साइबर सुरक्षा उल्लंघनों की जानकारी दी है। इन घटनाओं में कुछ ग्राहकों की जानकारी लीक हुई है या उस तक अनधिकृत पहुंच बनाए जाने की आशंका है। हालांकि, कंपनियों ने कहा है कि उनकी सेवाओं और भुगतान नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। ये खुलासे मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी और एक कार्डधारक लाभ कार्यक्रम से संबंधित हैं। एक रैनसमवेयर समूह ने हजारों ग्राहकों से संबंधित जानकारी लीक की है।

जेपी मॉर्गन, चेस, वीजा और मास्टरकार्ड ने अपने बाहरी सेवा प्रदाताओं (वेंडर्स) से जुड़े साइबर सुरक्षा उल्लंघनों की जानकारी दी है। इन घटनाओं में कुछ ग्राहकों की जानकारी लीक हुई है या उस तक अनधिकृत पहुंच बनाए जाने की आशंका है

जानकारी सुरक्षितः वीजा

वीजा ने अपने ग्राहकों से संबंधित दावों को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक सेवा प्रदाता से जुड़ी घटना से संबंधित बताया। कंपनी ने द रजिस्टर को बताया कि उसके अपने सिस्टम न तो इस घटना में शामिल थे और न ही प्रभावित हुए हैं। कार्ड नंबर जैसी भुगतान संबंधी जानकारी भी सुरक्षित रही है।

थर्ड पार्टी कंपनियों पर साइबर हमला किया गया

अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमला



एनजीरोएन नाम के रैंसमवेयर समूह ने करीब 16 हजार अमीर ग्राहकों का डेटा लीक करने की जिम्मेदारी ली है

जेपी मॉर्गन चेस ने गुरुवार को बताया कि उसके साथ काम करने वाली थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता कंपनियों पर साइबर हमला हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावरों ने इन कंपनियों के पास मौजूद कुछ मार्केटिंग डेटा तक पहुंच बनाई। इसमें ग्राहकों के नाम और ईमेल पते शामिल हो सकते हैं। रिपोर्टस के मुताबिक, एनजीरोएन नाम के रैंसमवेयर समूह ने करीब 16 हजार अमीर ग्राहकों का डेटा लीक करने की जिम्मेदारी ली है।

कामकाज पर असर नहीं

जेपी मॉर्गन ने कहा कि उसके मुख्य बैंकिंग कामकाज पर इस हमले का कोई असर नहीं पड़ा है। प्रभावित ग्राहकों से सीधे संपर्क किया जाएगा और उन्हें मुफ्त क्रेडिट मॉनिटरिंग समेत जरूरी सहायता दी जाएगी।

प्रभावितों की मदद कर रहेः मास्टरकार्ड

मास्टरकार्ड ने कहा कि यह घटना एक विशेष लाभ कार्यक्रम से जुड़े कार्डधारकों के एक छोटे समूह से संबंधित है। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेठ आइजन ने कहा कि डेटा के उजागर होने की घटना को नियंत्रित कर लिया गया है और कंपनी प्रभावित ग्राहकों की सहायता के लिए सेवा प्रदाता के साथ काम कर रही है।

लोग घबराएं नहीं: राष्ट्रपति ट्रंप



राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है। ट्रंप ने कहा कि लोगों को शांत रहना चाहिए, सब कुछ ठीक है। उन्होंने इन घटनाओं को अलग-अलग तकनीकी समस्याएं बताया और कहा कि मीडिया इन्हें जरूरत से ज्यादा चर्चा में ला रहा है। ट्रंप ने जेपी मॉर्गन चेस और अन्य संस्थानों की सेवाओं में आई रुकावट को सामान्य घटनाओं की तरह पेश किया।

अमेरिकी साइबर चीफ का इस्तीफा कर्स्टन डेविस लेंगी केर्नक्रॉस की जगह

अमेरिका के राष्ट्रीय साइबर निदेशक सीन केवनक्रॉस अपने से इस्तीफा दे दिया है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कर्स्टन ए. डेविस को ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर डायरेक्टर (ओएनसीडी) का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया। वह सीन केर्नक्रॉस की जगह लेंगी। नेशनल साइबर डायरेक्टर के स्थायी पद के लिए अमेरिकी सीनेट की मंजूरी जरूरी है।



कर्स्टन डेविस

खबर संक्षेप

डीआरआई ने 71 किलो हेरोइन की खेप जब्त की

चेन्नई। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने समुद्री तटीय मार्ग से श्रीलंका में तस्करी के लिए ले जाई जा रही 71 किलो से अधिक हेरोइन की खेप जब्त की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चेन्नई में 17 और 18 नवंबर को चलाए गए अभियान के दौरान यह जब्ती की गई है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

तट पर फंसा जहाज, 19 सदस्यों को बचाया

पेरिस। दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के लैंडेस क्षेत्र के तट पर माल्टा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज फंस गया। इसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाकर हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज पर मौजूद 19 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, जहाज को संभालने में मदद के लिए तीन क्रू सदस्य अब भी उस पर मौजूद हैं।

हूती विद्रोहियों का रियाद में टावर पर हमला

रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक टावर पर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी हुती विद्रोहियों ने ली है। हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सऊदी के नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने बताया है कि हमले में किंग अब्दुल्ला वित्तीय जिले की एक इमारत को नुकसान पहुंचा है।

प्रो. मांडे यूएन विशेषज्ञों के समूह में नियुक्त

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर शेखर सी. मांडे को संयुक्त राष्ट्र के दस उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों के समूह में 2026-2028 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना है।

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के बयान पर भारत ने दी प्रतिक्रिया

होर्मुज स्ट्रेट में जल्द शांति बहाल हो

ढाका के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम अच्छे संबंध चाहते हैं

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के बाद वहां के पीएम तारिक रहमान के बयान पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत का रुख पहले जैसा ही है। भारत बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को देखने वाला संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा संबंध, जिसकी जड़ें दोनों देशों के साझा इतिहास और वहां के लोगों के समान सांस्कृतिक मूल्यों में हों। तारिक रहमान के बयान पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भारत की सीमा से सटे उत्तर-पश्चिमी जिले लालमोनिरहाट में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि एक ग्रुप बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने उन्होंने आरोप लगाया कि अवामी लीग की सरकार ने न केवल देश और जनता के हितों की अनदेखी की, बल्कि सीमा पार अपने 'आकाओं' के हितों की भी सेवा की। देश से भागने के बाद भी उन्होंने एक बार फिर आगजनी और लोगों की हत्या की राजनीति शुरू कर दी है। वे पीछे से लोगों पर हमला कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका। हमें इन आतंकवादियों, आगजनी करने वालों और हत्यारों को स्पष्ट जवाब देना होगा। बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी की ओर से गुरुवार को आयोजित देशव्यापी बंद के दौरान कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुईं।

> विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को देखने वाला संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा संबंध, जिसकी जड़ें दोनों देशों के साझा इतिहास और वहां के लोगों के समान सांस्कृतिक मूल्यों में हों

जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता हो



रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय

बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाएं

जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की

होर्मुज स्ट्रेट में हाल में हुए हमलों को लेकर भारत ने अपनी चिंता दोहराई है। भारत सरकार ने कहा कि वह वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करती है। जयसवाल ने कहा कि इन हमलों में भारतीय नाविकों की जान गई है और कुछ घायल भी हुए हैं। कुछ हमले भारतीय झंडे वाले जहाजों पर भी हुए हैं। भारत ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। मंत्रालय ने बताया कि भारत का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल की जानी चाहिए।

पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के अनसार. पीएम बालेंद्र शाह 22 नवंबर को

नेपाल के पीएम 22-23 नवंबर को भारत आएंगे

दोनों देशों के बीच बेहद करीबी संबंध



पीएम बालेंद्र शाह

जयसवाल ने बताया कि नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह 22-23 नवंबर को भारत आएंगे। पीएम बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी, जिसमें वे राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात करेंगे। इसे राजकीय यात्रा का दर्जा दिया गया है। इस दौरान उन्हें सभी राजकीय सम्मान दिए जाएंगे।

जयसवाल ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से बेहद करीबी, दोस्ताना और बहुआयामी संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी नेटवर्क, स्टार्टअप, तकनीक, नवाचार, क्रिकेट और बुनियादी ढांचे के विकास में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। दोनों पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान भी करेंगे।

पाकिस्तान फिर बेनकाब

भारत दौरे पर आए मंत्री मलिक का स्वागत न करने का दावा झूठा



मुसादिक मसूद मलिक और साद वारैच

प्रोटोकॉल के तहत किया स्वागतः भारत

वहीं, विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि स्वागत प्रोटोकॉल के तहत मलिक की अगवानी के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक निदेशक और विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान (पीएआई) प्रभाग के एक अवर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) हवाई अड्डे पर मौजूद थे। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि नई दिल्ली आने वाले सभी एससीओ सदस्य देशों को इसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वहीं, नई दिल्ली आए मुसादिक मलिक ने कहा कि हमें संस्कृति और सभ्यताओं पर बात करनी चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि इन सभ्यताओं ने हम सभी को किस तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि वह बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं एससीओ का बहुत आभारी हूं कि वह ऐसे मंच आयोजित कर रहा है। ये मंच क्षेत्र के सभी देशों को एक साथ आने का मौका देते हैं। यहां ऐसे विचारों पर बात हो सकती है, जो

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पाकिस्तानी थिंक टैंक के एक विश्लेषक ने दावा किया था कि नई दिल्ली पहुंचने पर पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक का स्वागत करने के लिए कोई भी भारतीय अधिकारी मौजूद नहीं था।

खुर्रम अब्बास ने 'एक्स' पर आरोप लगाया कि एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मलिक के स्वागत के लिए भारत ने किसी अधिकारी को नहीं भेजा, जो कि शिष्टाचार के खिलाफ है। उनका स्वागत भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के सीडीए (चार्ज डी अफेयर्स) साद वारैच ने किया। बता दें. 2023 और मई 2025 के टकराव के बाद से भारत आने वाले वे पहले पाकिस्तानी मंत्री हैं।

निजामुद्दीन दरगाह जाने की नहीं दी अनुमति

पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन भारत सरकार ने उनकी मांग खारिज कर दी। वहीं, मलिक ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। ऐसे में सबसे आसान रास्ता उन मुद्दों पर बात करना है, जो सभी को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बड़े नजरिये से चीजों को देखेंगे। इस नजरिये में हम सभी राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। सभी सामाजिक मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। बातचीत से जुड़े हर मुद्दे को देखेंगे। साथ ही पूरे क्षेत्र के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे।

भारत-फ्रांस के बीच जेडब्ल्यूजी बैठक

आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुए 'सहमत'

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली



भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हुए इसके खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 18वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोधक मामलों के अतिरिक्त सचिव डॉ. सुहेल एजाज खान और फ्रांस के आतंकवाद निरोधक एवं संगठित अपराध मामलों के विशेष दूत तथा एंबेसडर एट लार्ज ऑलिवियर केरन ने की। दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। उन्होंने पहलगाम और दिल्ली में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की।

भारत-पुर्तगाल के बीच 5 वर्षीय रोडमैप

व्यापार, निवेश, रक्षा सहित कृषि क्षेत्र में बढ़ाएंगे द्विपक्षीय सहयोग

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली



भारत और पुर्तगाल ने आपसी संबंधों के लिए व्यापक पांच वर्षीय रोडमैप (2027-2032) को अंतिम रूप देने की साझा प्रतिबद्धता जताई। यह रोडमैप अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग की दिशा तय करने पर काम करेगा। दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े स्थापित संस्थागत तंत्रों की नियमित बैठकों का भी स्वागत किया। साथ ही सभी क्षेत्रों में सहयोग और संपर्क को और गहरा करने पर सहमति जताई। भारत और पुर्तगाल के बीच विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) की छठी बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय में विदेश नीति महानिदेशक हेलेना मालकाटा ने की।

थल सेनाध्यक्ष ने चेक आर्मी ब्रिगेड का दौरा किया



नई दिल्ली। थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल धीरज सेठ ने शुक्रवार को चेक थल सेना की चौथी 'रैपिड डिप्लॉयमेंट ब्रिगेड' का दौरा किया। इस दौरान उन्हें ब्रिगेड की संरचना, कार्यक्षेत्र और क्षमताओं की विस्तृत जानकारी दी गई। भारतीय थल सेना ने 'एवस' पर पोस्ट कर बताया कि इस दौरे से सेठ सेना के जवानों के साथ बातचीत करने और उनकी तैयारियों, क्षमताओं तथा कार्यप्रणालियों को समझने का मौका मिला। इससे दोनों देशों के बीच पेशेवर सैन्य संबंधों और रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलेगी। जनरल सेठ चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस से स्नातक हुआ पहला बैच

भारत-यूएई ने एआई और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय चर्चा की

एजेंसी ▶▶ दुबई

शिक्षा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर के पहले बैच के विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। दुबई में जोशी ने यूएई के एआई, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रिमोट वर्क एप्लीकेशंस मामलों के राज्य मंत्री उमर सुल्तान अल ओलमा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में एआई आधारित शिक्षा, शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने तथा कक्षाओं में उभरती प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषय शामिल रहे।



अबू धाबी कैंपस में छात्रों को डिग्रियां वितरित करते हुए

संयुक्त अनुसंधान पर विचार-विमर्श

दोनों मंत्रियों ने संयुक्त एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने में आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इसके अंतर्गत मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सहयोग और अकादमिक तथा अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना के अंतर्गत एआई, जलवायु अनुकूलन क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान पर विचार-विमर्श हुआ

युद्धपोतों के रखरखाव में भारत स्थापित कर रहा वैश्विक पहचान

अमेरिकी नौसेना के पांचवें जहाज की कट्टुपल्ली में होगी मरम्मत

एजेंसी ▶▶ चेन्नई

अमेरिकी नौसेना का आपूर्ति पोत यूएसएनएस वैली शिर्श शुक्रवार को चेन्नई के पास एलएंडटी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड पहुंचा। यहां भारत-अमेरिका मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट (एमएसआरए) के तहत जहाज की मरम्मत की जाएगी। यह अमेरिकी नौसेना के मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड (एमएससी) का हिस्सा है, जो दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य और सरकारी एजेंसियों को समुद्री परिवहन, रसद और विशेष समुद्री सहायता उपलब्ध कराता है। कट्टुपल्ली शिपयार्ड में किसी अमेरिकी नौसैनिक जहाज की मरम्मत का यह पांचवां अवसर है। इसे भारत के जहाज मरम्मत ढांचे और तकनीकी क्षमताओं पर अमेरिका के बढ़ते भरोसे के रूप में देखा जा रहा है।

अच्छी खबर



अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट किया

कट्टुपल्ली शिपयार्ड पर अमेरिकी नौसेना युद्धपोत वैली शिर्श

2022 में शुरू हुआ था सहयोग

भारत और अमेरिका के बीच जहाज मरम्मत में सहयोग अगस्त 2022 में शुरू हुआ था। चार्ल्स डु भारतीय शिप्यार्ड में मरम्मत कराने वाला अमेरिकी नौसेना का पहला जहाज बना था। इसके बाद मार्च 2023 में मैथ्यू पैरी और जुलाई 2023 में रेनेवर की मरम्मत की गई। इसके बाद अप्रैल 2023 में एलएंडटी ने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।

चालक दल की सुगमता के लिए संशोधित एसओपी

यूएसएनएस वैली शिर्श संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू होने के बाद मरम्मत के लिए भारत पहुंचने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज है। यह एसओपी जहाज के चालक दल के सदस्यों के भारत में प्रवेश और प्रस्थान की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। इसे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आव्रजन ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय और रक्षा उत्पादन विभाग के समन्वित प्रयासों से अंतिम रूप दिया।

समुद्री सहयोग को मिली मजबूती

अमेरिकी नौसेना के इन पांच जहाजों की मरम्मत से अंतरराष्ट्रीय जहाज मरम्मत परिचालन को बढ़ावा देने और समुद्री औद्योगिक सहयोग मजबूत करने के भारत के प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है।

भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति और शिल्प परंपराओं की बिखरी अनुपम छटा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

नई दिल्ली - भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपराओं और शिल्प कौशल की मनोहारी झलक देखने को मिल रही है। मेले में स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय अस्मिता और पारंपरिक हस्तशिल्प की विशिष्ट पहचान को प्रदर्शित कर रहा है। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का निरीक्षण कर वहां प्रदर्शित विभिन्न कलाकृतियों, पारंपरिक वस्त्रों, कोसा रेशम तथा जनजातीय संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्पकला, हस्तनिर्मित उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत के विविध स्वरूपों की जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश के शिल्पकारों की कलात्मक प्रतिभा, परंपरागत कौशल और पीढ़ियों से संरक्षित सांस्कृतिक धरोहर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोककला, जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प हमारी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण आधार हैं। इनका संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ पवेलियन में प्रदर्शित कोसा रेशम से निर्मित वस्त्र, पारंपरिक परिधान और हस्तशिल्प उत्पाद प्रदेश की विशिष्ट शिल्प परंपराओं का परिचय दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कोसा रेशम अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्ट बुनाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जनजातीय जीवनशैली से प्रेरित कलाकृतियां



प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, लोकविश्वास, परंपराओं और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव को अभिव्यक्त कर रही हैं। डॉ. कन्नौजे ने कहा कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जैसे प्रतिष्ठित आयोजन छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक शिल्प, हस्तनिर्मित उत्पादों और जनजातीय कलाओं को व्यापक पहचान मिलने के साथ ही स्थानीय कलाकारों एवं शिल्पकारों के लिए नए अवसरों की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत केवल हमारी ऐतिहासिक पहचान ही नहीं, बल्कि लोकजीवन, परंपराओं और सामुदायिक मूल्यों की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में प्रचलित लोककलाएं, पारंपरिक वस्त्र, शिल्पकला और जनजातीय परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाती हैं। इन परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठित करना अत्यंत आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अपनी विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, बेलमेटल शिल्प, ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प तथा कोसा वस्त्रों के लिए विशेष पहचान रखता है। प्रदेश की पारंपरिक कलाओं में स्थानीय समुदायों की जीवनशैली, प्रकृति के प्रति आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही कलात्मक परंपराओं की झलक दिखाई देती है। इन कलाओं का संरक्षण सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ-साथ पारंपरिक शिल्प से जुड़े समुदायों की आजीविका और आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि, पारंपरिक शिल्प कौशल और जनजातीय अस्मिता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत को व्यापक मंच प्रदान करने के साथ ही प्रदेश की कला, संस्कृति और शिल्प परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की धूमः 7 दिनों से निकल रही प्रभात फेरी, कल सजेगा भव्य नगर कीर्तन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

पत्थलगांव। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर नगर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल है। गुरुद्वारा साहिब को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है और शहर की गलियां सुबह-सुबह गुरु की वाणी व शबद-कीर्तन से गूंज रही हैं। 50 वर्षों से चली आ रही इस गौरवशाली परंपरा को यादगार बनाने के लिए सिख समाज के सभी वर्ग सामूहिक रूप से जुटे हुए हैं।



घर-घर पहुंच रहा गुरु का संदेश

पर्व के उपलक्ष्य में पिछले सात दिनों से नगर में प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि प्रभात फेरी प्रतिदिन समाज के किसी एक परिवार या प्रतिष्ठान तक जाती है, जहां सामूहिक अरदास व कीर्तन के बाद जलपान की व्यवस्था की जाती है। इसके माध्यम से गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और प्रेम का संदेश घर-घर तक पहुंच रहा है।

कल पंज प्यारों की अगुवाई में निकलेगी भव्य शोभायात्रा

प्रकाश पर्व का मुख्य आकर्षण 22 नवंबर (रविवार) को निकलने वाली भव्य शोभायात्रा (नगर कीर्तन) होगी। पंज प्यारों की अगुवाई में निकलने वाले इस नगर कीर्तन में गतका दल के हैरतअंगेज करतब, कीर्तन जत्थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। शोभायात्रा के स्वागत के लिए पूरे नगर में विशेष तैयारियां की गई हैं।

24 को अखंड पाठ की समाप्ति व अटूट लंगर

24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मुख्य पर्व पर गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति होगी। इसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा, जहां सभी वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करेंगे।

समाज के सामूहिक सहयोग से हो रहे आयोजनः भाटिया

गुरुसिंह सभा के अध्यक्ष हरजीत सिंह भाटिया ने बताया कि प्रकाश पर्व पर सेवा और अटूट लंगर का विशेष महत्व है। नगर कीर्तन से लेकर गुरुद्वारा साहिब में होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां समाज के सामूहिक सहयोग से पूरी कर ली गई हैं। बाहर से आने वाले जत्थों और श्रद्धालुओं के स्वागत व ठहरने के लिए भी गुरुसिंह सभा द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं।

हाई कोर्ट के दखल से झुका शिक्षा विभाग, महिला व्याख्याता को मिला चाइल्ड केयर लीव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर : अपने पांच वर्षीय मासूम बेटे की देखभाल और पैर के लिगामेंट की चोट के बीच जूझ रही एक महिला व्याख्याता को आखिरकार न्याय मिला है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने व्याख्याता राजश्री कौशिक का संतान पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) मंजूर कर लिया है। अवकाश स्वीकृति का आदेश अदालत के समक्ष भी पेश कर दिया गया है।

लिगामेंट की चोट ने बढ़ाई मुश्किल, खारिज हुआ था आवेदन

सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय, बिलासपुर में व्याख्याता (क्लास-2) के पद पर पदस्थ राजश्री कौशिक के बाएं पैर में चोट लगने से लिगामेंट डैमेज हो गया था। शारीरिक तकलीफ और अन्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनके लिए पांच वर्षीय पुत्र देवांश की समुचित देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने 28 सितंबर 2026 को डीईओ कार्यालय में संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन दिया था, जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के जरिए हाई कोर्ट की शरण ली।



'अवकाश अधिकार है, प्रशासनिक बहाने नहीं चलेंगे'

जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38(सी) का हवाला दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि महिला शासकीय कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की परवरिश और सुरक्षा के लिए कुल 730 दिन का संतान पालन अवकाश लेने की पात्रता है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह महिला कर्मी का अधिकार है और केवल स्टाफ की कमी या प्रशासनिक कारण बताकर इसे रोका नहीं जा सकता।

कोर्ट में पेश हुआ स्वीकृति आदेश

हाई कोर्ट के हस्तक्षेप और सख्त रुख के बाद शिक्षा विभाग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। डीईओ बिलासपुर ने राजश्री कौशिक का अवकाश स्वीकृत करते हुए आदेश जारी किया और इसकी प्रति न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दी।

बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होंगी सभी कक्षाओं की छमाही परीक्षाएं, कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर, जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर अजीत वसंत ने स्कूल शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी कक्षाओं की आगामी छमाही परीक्षा बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, जेईई-नीट की तैयारी, अपार आईडी निर्माण, छात्रवृत्ति तथा विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित अपार आईडी के कारणों की जानकारी एक सप्ताह में प्रस्तुत करने तथा कक्षा पहली के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र शत-प्रतिशत बनाने के निर्देश दिए।

बोर्ड की तर्ज पर छमाही परीक्षा

सभी कक्षाओं की आगामी छमाही परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के अनुरूप होंगी। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को पर्यवेक्षक (इनविजिलेटर) बनाया जाएगा और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी दूसरे स्कूलों के शिक्षक करेंगे।

अपार आईडी और प्रमाण पत्र

जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बनी है, उनके कारणों की सूची एक सप्ताह में मांगी गई है। साथ ही आधार समस्याओं का शीघ्र निराकरण, पहली कक्षा के बच्चों के शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र व बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा।

आरटीई की निगरानीः

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेशित कोई बच्चा यदि बीच सत्र में स्कूल छोड़ता है, तो स्कूल को 7 दिनों के भीतर कारण सहित विभाग को सूचित करना होगा।



जेईई-नीट व सरगुजा-30:

जेईई-नीट की ऑनलाइन कक्षाओं, टेस्ट सीरीज और छूटी कक्षाओं के लिए रिकॉर्डेड वीडियो की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। चयन न होने वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग करने और रायपुर में कोचिंग ले रहे छात्रों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

शिक्षकों की उपस्थिति व रिक्त पदः

वीएसके ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित जांच, अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई और विषय शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। लंबित पेंशन प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदुः

जर्जर स्कूल भवनों, शौचालयों और किचन शेड के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, ईंट भट्ठों में काम करने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी जैसी कार्ययोजना बनाने तथा केंद्रीय जेल और 'उल्लास' साक्षरता कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए

बेटी का शव चौराहे पर रखकर परिजनों ने लगाया जाम

अमेठी, शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार सुबह वे शव लेकर रामगंज चौराहे पहुंच गए और सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने में जुट गए।

तीन चक्रवाती तूफानों से किसानों का फसल बर्बाद सरकार मुआवजे का आंकलन भी नहीं करवा रही - दीपक बैज

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि पिछले 24 दिनों में तीन चक्रवाती तूफानों के कारण किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। यह तीनों तूफान ऐसे समय आये है, जब किसानों की फसल तैयार हो गयी है। अभी अकवान तूफान के समय बहुत से किसानों का धान खरीदी केन्द्रो पर पहुंच चुका है। वहां पर बे-मौसम बारिश से भीग गया है। बहुत से किसानों का धान बेमौसम बारिश से गिर गया है। लाखो किसानों का धान अभी खेतो में कटकर करपा पड़ा था। बियारा तक नहीं आया है तथा भीग कर वही खराब हो गया है। बस्तर क्षेत्र में पहले ही 1083 गांवो के 74 हजार से अधिक लोग और 6154 हेक्टेयर से ज्यादा फसल प्रभावित हो चुकी है। पूरे प्रदेश में लाखों हेक्टेयर धान की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन यह सरकार गंभीर नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले दो तूफानों अनंव और मुरासु से हुए नुकसान के आंकलन का सर्वे सरकार की तरफ से नहीं करवाया गया है। तीसरे तूफान अकवान का अभी प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। किसानों के नुकसान के आंकलन के लिये कोई प्रयास नहीं किये जाने से सरकार की नीयत में खोट दिख रही है। अब जबकि चक्रवाती तूफान ह्यअकवानह्न आया हुआ है, बहुत से किसान धान बेचने के लिये अपना टोकन कटवा चुके थे, लेकिन तीन चार दिनों से खराब मौसम के कारण वे धान नहीं बेच पाये है, उनका टोकन लेप्स हो गया



है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि तीनो तूफान के समय से ही पटवारी हड़ताल में है। सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त करवाने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं किया। पटवारी के माध्यम से ही फसलो के नुकसान का आंकलन करवाया जाता है। पटवारियो के हड़ताल से आंकलन नहीं हो पा रहा। सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं देख रही। मतलब फसल क्षतिपूर्ति नहीं देना चाहती है। निजी फसल बीमा कंपनिया सरकार के संरक्षण में मोटा मुनाफा कमा रही है, प्रीमियम जमा करके भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसान इस सरकार की बदनीयती से बर्बाद हो रहे है।

कांग्रेस पार्टी मांग करती है

सरकार तत्काल तीनो तूफानो से हुए नुकसान का आंकलन कर के क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करें।

बीमा कंपनियों को सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया जाये कि वे तत्काल फसलों के नुकसान का आंकलन कर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करें। राजस्व नियम के आपदा राहत प्रावधान के तहत राजस्व पुस्तिका 6/4 के अनुसार भी मुआवजा प्राप्त करना किसानों का अधिकार है, जिस पर ये सरकार गंभीर नहीं है। सभी ब्लाको में कृषि अधिकारियो को नोडल अधिकारी बना कर फसल बीमा राशि प्रदान करने बीमा कंपनियो का निगरानी कराये। क्षतिपूर्ति की गणना प्रति एकड़ 21 क्विंटल के उत्पादन तथा 3100 रू. प्रति क्विंटल के मूल्य से की जाये। अर्थात धान के लिये 65100 रू. प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति तत्काल घोषित करे। जो किसान ने तीन दिनों से टोकन कटवा कर धान नहीं बेच पाये है, उनका टोकन फिर से जारी किया जाये। मौसम की स्थिति को देखते हुये धान खरीदी की तिथि अभी से 15 दिन और बढ़ाने की घोषणा की जाये। सरकार पटवारी हड़ताल समाप्त करने के लिये तत्काल पहल करे।

GST की महिला अधिकारी 1.50 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बिचौलिया भी पकड़ाया; घर पर ACB की रेड

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

कांकेर - एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग की अधिकारी के कांकेर स्थित आवास पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी की राशि कम करने के एवज में एक व्यवसायी से डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में यह कदम उठाया गया है। आरोपी अधिकारी की पहचान जीएसटी अधिकारी अर्चना गिरी के रूप में हुई है। एसीबी को व्यवसायी की तरफ से शिकायत मिली थी कि अधिकारी कर की रकम घटाने के बदले डेढ़ लाख रुपये की अनुचित मांग कर रही हैं। शिकायत मिलते ही भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो की टीम ने मामले का सत्यापन किया और अधिकारी को पकड़ने के लिए



दी। शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एसीबी के अधिकारी रिश्वत के लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं।

रकम छोड़ते ही दबिश

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। तय योजना के तहत व्यवसायी रिश्वत की रकम लेकर अधिकारी अर्चना गिरी के घर पहुंचा। व्यवसायी जैसे ही अधिकारी के घर पर डेढ़ लाख रुपये की रकम छोड़ बाहर निकला, उसी समय पहले से सतर्क खड़ी एसीबी टीम ने मकान में दबिश दे दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के इलाके में हलचल मच गई।

निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी और गुणवत्ता से कोई समझौता नही : बंसल

0 लोनिवि सचिव ने जांची सड़को की गुणवत्ता 0 लापरवाही पर ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने और ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश





प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल लगातार दो दिनों से सड़कों, पुल-पुलियों, कॉलेजों, अस्पताल और अन्य निर्माण एवं संधारण कार्यों का सघन निरीक्षण किया। श्री बंसल ने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार और सड़क संधारण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने, बैंक गारंटी राजसात करने तथा सुधार नहीं होने पर ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी, गुणवत्ता मानकों के पालन और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया।लोक निर्माण के सचिव श्री बंसल ने प्रमुख अभियंता व्ही.के. भतपहरी, अंबिकापुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता के.पी. संत, अंबिकापुर मंडल के अधीक्षण अभियंता आर.एस. तोमर तथा संबंधित संभागों के कार्यपालन अभियंताओं व अनुविभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों के साथ, प्रतापपुर, भैयाथान और सूरजपुर में सड़कों की स्थिति तथा विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने सड़क संधारण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।सूरजपुर जिले में सचिव श्री बंसल ने बिशुनपुर, सूरजपुर-ओड़गी मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क पर डामरीकरण तत्काल प्रारंभ करने तथा उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए।उन्होंने 27 किलोमीटर लंबे तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर-कृष्णपुर मार्ग के निर्माण कार्य की भी प्रगति देखी। निरीक्षण के दौरान ठेकेदार ने बताया कि लगभग 10 किलोमीटर सड़क पर डब्ल्यूएमएम का कार्य पूरा कर लिया गया है। बैच मिक्स प्लांट भी स्थापित हो चुका है। अगले तीन-चार दिनों में प्लांट के कैलिब्रेशन सहित आवश्यक कार्य पूर्ण कर डामरीकरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठेकेदार ने जून 2027 तक अनुबंध के सभी कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इस पर सचिव श्री बंसल ने डामरीकरण जल्द शुरू कर निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।श्री बंसल ने सूरजपुर स्थित कलेक्टर बंगले में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, सूरजपुर ऑडिटोरियम के मरम्मत कार्य तथा जिले में निर्माणाधीन अन्य कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।दो दिवसीय निरीक्षण के दौरान सचिव श्री बंसल ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, सड़क संधारण में तत्परता तथा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

लियाफी की नई कार्यकारिणी में आमिर साय चुने गए जिलाध्यक्ष



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शनिवार को लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थानीय इकाई का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में संगठन के नए पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया। नई टीम के गठन के साथ ही जिले में एलआईसी अभिकर्ताओं के हितों, अधिकारों और सम्मान की आवाज को मजबूती देने की दिशा में संगठनात्मक पहल की गई है। चुनाव अधिकारी सुनील निगम, जोनल उपाध्यक्ष एवं संतोष कुमार देवानी, मंडल संगठन सचिव, शहडोल मंडल की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। चुनाव के दौरान संगठन को मजबूत बनाने और अभिकर्ताओं की समस्याओं को एकजुट होकर उठाने के उद्देश्य से नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। चुनाव में आमिर साय को अध्यक्ष चुना गया। वहीं संदीप शर्मा उपाध्यक्ष व आगरसाय राजवाड़े सचिव चुने गए है। शिवशंकर राजवाड़े, यशोदा साहू एवं बसंती साहू को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन सचिव के रूप में सुरेंद्र गुप्ता एवं सुनीता सिंह का चयन किया गया। तपेश्वरी राजवाड़े को सह सचिव तथा एमडी सुलतान को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। संगठन के संरक्षक मंडल में अशोक साहू, हृदयराम राजवाड़े, हुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, धनंजय उपाध्याय, सोमारू राम एवं सजीवन जायसवाल को शामिल किया गया।कार्यकारिणी सदस्य के रूप में वैजनाथ राजवाड़े, रामसूरत राजवाड़े, साहिना खान, लुहांसी साहू, सुशीला सिंह एवं शांति सिंह को शामिल किया गया। लियाफी का प्रमुख उद्देश्य जीवन बीमा अभिकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा, कमीशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य मांगों को उचित मंच पर उठाना है। सूरजपुर में नई कार्यकारिणी के गठन को अभिकर्ताओं को संगठित करने और उनकी समस्याओं को सामूहिक रूप से सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई टीम से उम्मीद जताई जा रही है कि वह संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी तथा अभिकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करेगी। चुनाव पश्चात नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को शुभकामनाएं दी गईं।

शराब के नशे में हुए मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या

आरोपी गिरफ्तार, तेलसरा में हुई वारदात



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शराब के नशे में मदहोश पति ने मामूली सी बात पर टांगी से प्रहार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। हत्या की उक्त वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम तेलसरा में हुई है। आरोपी पति ने सुबह खुद से पड़ोसियों को पत्नी की हत्या करने की बात बताई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। बताया गया है कि तेलसरा का जयकरण लोहार और उसकी पत्नी उर्मिला के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बीती रात भी शराब के नशे में जयकरण का पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर जयकरण ने पास में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी उर्मिला की गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे वह रक्तरंजित होकर वहीं पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रात को हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सुबह आरोपी खुद पड़ोसियों के पास पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। जानकारी लगने के बाद पड़ोसियों द्वारा घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी पति जयकरण लोहार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली गई है।

तीन दिनों से लापता युवक का सड़क के किनारे मिला शव, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शनिवार की सुबह शहर के रिंगरोड स्थित छठ घाट के समीप एक युवक का शव सड़क के किनारे संदिग्धावस्था में पाया गया है। मृतक की पहचान सतपाल सिंह चावला उर्फ राजू के रूप में हुई है। मूलतः एमसीबी जिले के चिरमिरी का रहने वाला उक्त युवक शहर के अग्रेसन वार्ड में रहता था जो पेशे से बाईक मिस्त्री था। बताया गया है कि युवक बीते तीन दिनों से बगैर घर में किसी को कुछ बताए कहीं चला गया था। परिजन उसकी पतासाजी में लगें हुए थे मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका था। शनिवार की सुबह छठ घाट के समीप युवक का शव पाया गया है।

घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना के बाद शव को पीएम के लिए भिजवाया गया तथा पीएम पश्चात पुलिस ने शव परिजनों को सौप दिया है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है इसकी वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगी।



फसल आज भी खड़ी है, फिर भी 15 को बिक गया 42 क्विंटल

धमतरी, (एजेंसी)। हिंचापुर खसरा 124 के फर्जी धान खरीदी मामले में अब विभागीय प्रक्रिया पर सवाल उठता है। फसल आज भी खड़ी है, इसके बाद भी 15/11/2026 को टोकन नंबर टीके 590019012627 00 पर 42 क्विंटल धान की बिक्री दिखा दी गई। एग्रीस्टैक में तरुण पिता मोहन सिन्हा, ग्राम साँकरा के नाम पर सिर्फ खसरा 124, रकबा 0.4800 हेक्टेयर दर्ज है।

हार्वेस्टर लाया था, आवेदक ने काटने नहीं दिया

आवेदक प्रेम नारायण सिन्हा का कहना है कि शिकायत के बाद मामले को दबाने और ये साबित करने के लिए कि उसी खेत का धान बिका है, धान काटने के लिए हार्वेस्टर लाया गया था।

लेकिन आवेदक के मना करने पर धान नहीं काटा गया। धान काटा नहीं गया है, अभी भी फसल खड़ी है।

अगर 15 तारीख को ही धान बिक गया था, तो खेत में आज भी फसल खड़ी क्यों है?

18, 20 और 21 को हुआ पंचनामा, तीनों दिन फसल खड़ी पाई गई

18 तारीख को : पटवारी, कोटवार सहित आवेदक की उपस्थिति में पंचनामा हुआ, फसल खड़ी पाई गई।



20 तारीख को : एसडीओपी के निर्देश पर विभागीय और उपार्जन केंद्र के कर्मचारी व आवेदक उपस्थित थे, फसल खड़ी पाई गई।

21 तारीख को : फिर पंचनामा हुआ, फसल खड़ी पाई गई।

तीनों दिन के पंचनामे और जियोटैग फोटो-ग्राफ में यही साबित हुआ है कि फसल कटी ही नहीं है। कटाई के समय पंचनामा के लिए समिति को खबर किया गया था, लेकिन समिति का कोई आदमी नहीं आया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सरपंच व अन्य ग्रामवासियों से पंचनामा कराया।

19 तारीख को : तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कृषि अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे।

विभागीय प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठता है?

1. शिकायत के बाद भी भुगतान की फाइल कैसे बनी? : 15 को बिक्री, 16 को बैंक ने पेमेंट की फाइल बना ली, जबकि शिकायत पहले ही दी जा चुकी थी। विभागीय प्रक्रिया कहती है पहले सत्यापन, फिर भुगतान। यहां उल्टा हुआ।

2. सत्यापन के बिना खरीदी कैसे हुई? : नीति के अनुसार संदेह होने पर खरीदी रोककर नोडल अधिकारी को सूचना देनी थी और खेत का भौतिक सत्यापन करना था। यहां न खरीदी रोकी गई, न सूचना दी गई, न सत्यापन हुआ।

3. समिति पंचनामे में क्यों नहीं आई? : हार्वेस्टर लाने और पंचनामे के समय समिति को बुलाया गया, लेकिन समिति का कोई आदमी नहीं आया। विभागीय प्रक्रिया में समिति की उपस्थिति अनिवार्य थी।

4. 18, 20, 21 के पंचनामे के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? ड्ड तीन-तीन बार पंचनामे में फसल खड़ी पाई गई, फिर भी टोकन निरस्त नहीं हुआ, भुगतान नहीं रोका गया, FIR नहीं हुई। तो विभागीय प्रक्रिया कहां अटकी है?

बीईओ प्रतापपुर के कार्यकाल की शिकायतों पर डीईओ ने कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को भेजा प्रस्ताव

वर्षों से पदस्थ बीईओ पर प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना का आरोप

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रतापपुर के प्रभारी बीईओ की कार्यप्रणाली को लेकर मामला अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। लगभग 8-9 वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थ रहने और उनके कार्यकाल के दौरान सामने आई विभिन्न शिकायतों को लेकर उठे सवालों के बीच जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजे हैं। मामला केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि विभागीय दस्तावेजों में वर्ष 2025 से जुड़े कई प्रशासनिक प्रकरणों, युक्तियुक्तकरण में कथित अनियमितताओं और कारण बताओ नोटिसों के जवाब नहीं मिलने का उल्लेख है।

इस पूरे मामले को लेकर ग्राम पोड़ी के चंद्रिका कुशवाहा ने 5 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत कर प्रभारी बीईओ मुन्नू सिंह धुर्वे के लंबे कार्यकाल, विभागीय कार्यप्रणाली, लंबित शिकायतों और प्रशासनिक निर्देशों के पालन में कथित लापरवाही की निष्पक्ष जांच हेतु मांग की थी। इस मामले में सबसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आधिकारिक पत्रों से सामने आया है। कलेक्टर के पत्र क्रमांक 5949/स्था.01/टी-संवर्ग/2025 दिनांक 21 अगस्त 2025 के माध्यम से बीईओ के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर भेजे जाने का उल्लेख है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने पत्र क्रमांक 8593/स्था.01/टी-संवर्ग/2025 दिनांक 6 नवंबर 2025 को आयुक्त सरगुजा को अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा। इस पत्र में कलेक्टर द्वारा अनुमोदन का भी उल्लेख किया गया है। इसकी प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर सूरजपुर और संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग को भी भेजी गई थी।

प्रस्ताव में बीईओ के कार्यकाल के दौरान सामने आए विभागीय मामलों का विवरण देते हुए प्रशासनिक लापरवाही, शासकीय निर्देशों के पालन में कमी और कारण बताओ नोटिसों के जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने जैसे बिंदु दर्ज किए गए हैं। विशेष रूप से वर्ष 2025 में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान प्रतापपुर विकासखंड के विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। हाईस्कूल गणेशपुर, माध्यमिक शाला खोरमा, कन्या प्रतापपुर और प्राथमिक शाला दुरती सहित कई विद्यालयों के मामलों को विभागीय प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इसके अलावा व्याख्याता प्रियंका पाण्डेय से संबंधित जानकारी और प्राथमिक शाला यादवपारा दुरती में रिक्त पद की सूची में शामिल नहीं किए जाने का मामला भी दर्ज है। 14 अक्टूबर 2025 की विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन और विद्यालयों के परीक्षा परिणाम की सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। इन मामलों के आधार पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। जनदर्शन में शिकायत के बाद 22 अक्टूबर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने पत्र जारी कर शिकायतकर्ता को विभागीय कार्रवाई के प्रस्तावों की जानकारी दी। पत्र में स्पष्ट किया गया कि संबंधित प्रकरणों की जानकारी उच्च कार्यालय को भेजी जा चुकी है और वहां से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।



ज्ञान के दान से युवाओं के भविष्य को संवारने की पहल, राखी देवांगन ने किया पुस्तकों का दान

रायपुर, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की पहल से जिले में संचालित स्मृति पुस्तकालय योजना और सेवा संकल्प जैसे जनभागीदारी के प्रयास समाज में शिक्षा एवं सेवा की भावना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन पहलों से प्रेरित होकर आम नागरिक भी जरूरतमंद विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक-4 के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में कार्यरत राखी देवांगन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस एवं वीरांगना शौर्य उत्सव के अवसर पर सेवा संकल्प के तहत पुस्तकों का दान किया। उनका यह योगदान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा।



नवंबर के महीने में कुदरत का अचानक बदला मिजाज

आसमान से बरसी आफत ने किसानों की बढ़ाई धड़कनें!

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। जिले में 21 नवंबर को हुई अचानक बारिश ने मौसम के मिजाज को अचानक बदल दिया है। कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) से जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 137.8 mm वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें जशपुर (32.0 mm) और सन्ना (30.5 mm) सबसे अधिक प्रभावित रहे। नवंबर के तीसरे सप्ताह में हुई इस बारिश का सीधा असर जिले की खेती-किसानी, बाजार व्यवस्था और मौसमी के जनजीवन पर पड़ने की संभावना दिख रही है।

खेती पर संभावित प्रभाव, कटाई और मड़ाई की चुनौती

जशपुर जिले में नवंबर का समय खरीफ खेती, देसी धान की कटाई, मिसाई और कटाई में फसल सुरक्षित रखने के खेतों से बेहद संवेदनशील माना जाता है। पकी धान की फसल पर खतरः जिन इलाकों में धान की कटाई हो चुकी है और फसल खेतों या कटाई में रखी है, वहां नमी बढ़ने से दाने खराब होने, रंग बदलने या अंकुरण की आशंका बढ़ सकती है।

कटाई में देरी

जशपुर, सन्ना, बगीचा, कुंकुरी और कांसाबेल जैसे क्षेत्रों में 24 से 32 मिमी तक हुई बारिश के कारण खेतों में कीचड़ और नमी से कटाई के काम में अस्थायी असर आ सकती है। रबी और उद्यानिकी फसलों को लाभ या जोखिमः जहां एक ओर रबी खेती (जैसे चना, सरसों, गेहूं आदि) की बुवाई या प्रारंभिक नमी के लिए यह पानी कुछ हद तक सहायक हो सकता है, वहीं अधिक नमी या जलभराव की स्थिति में सब्जियों और उद्यानिकी फसलों को फफूंद या गलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

सुखाई और भंडारण

किसानों के लिए कटी हुई फसल को सुखाना और सुरक्षित भंडारण करना अगली बड़ी चुनौती रहेगी। जनजीवन और मौसम पर असर पहाड़ी और वनच्छादित भूगोल वाले जशपुर जिले में बेमौसम बारिश अक्सर तापमान में गिरावट और बर्फबारी की सक्रिय साथ किसानों को मिलती है। ठंड में उगनाः बारिश और बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट तथा सुबह-रात की ठंड बढ़ने की संभावना है। एनएचआई ऊंचाई वाले और वनांचल क्षेत्रों जैसे सन्ना, बाग और जशपुर में सर्दी का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है।

बर्फबारी और दैनिक कार्य

अचानक हुई बारिश से ग्रामीण कच्चे तालमेल, बाजरा और साप्ताहिक हाट-बाजारों की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। वहीं मनोरा, दुलदुला, पत्थलगांव और बागबहार में 0.0 मिमी वर्षा दर्ज होने से जिले के भीतर मौसम का मिजाज देखने को मिला।

स्वास्थ्य और सूक्ष्म

बदलाव मौसम और ठंड बढ़ने के साथ सर्दी-जुकाम तथा मौसमी बीमारियों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं किसानों को फसल सुरक्षा के लिए तिरपाल आदि की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा।

किसानों और नागरिकों के लिए व्यावहारिक सुझाव

तैयारियों और खेतों में रखी कटी फसल को तिरपाल या पॉलीथिन से ढककर रखें और जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। फसल के नुकसान या आर्द्रता से जुड़ी किसी भी स्थिति के लिए स्थानीय कृषि विभाग या राजस्व अमले से संपर्क बनाए रखें। बदलते मौसम को देखते हुए गर्म कपड़ों का उपयोग करें और यात्रा के दौरान मार्ग की स्थिति का ध्यान रखें।

घर में छिपा रखा था 4 लाख का गांजा, ग्राहक ढूंढते आरोपी को पुलिस ने नोवोटा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



जशपुर। ऑपरेशन हमले के तहत जशपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम बंगुरकेला में 8.250 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की नकली कीमत लगभग 4 लाख रुपये बताई जा रही है।आरोपी अपने घर में गांजा छिपाकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा था, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे धर नोवोटा। आरोपी राजकुमार दानी, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बंगुरकेला अखराडीपा, थाना दुलदुला, जिला जशपुर (छ.ग.) के खिलाफ थाना दुलदुला में अपराध क्रमांक 75/26 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मुखबिर की सूचना पर हुई दबिश

थाना दुलदुला पुलिस को 20 नवंबर को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम बंगुरकेला अखराडीपा निवासी राजकुमार दानी अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा भारी मात्रा में छिपाकर रखा है तथा बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर थाना दुलदुला पुलिस ने उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा गवाहों के स्पष्टीकरण संदेही राजकुमार दानी के मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मकान के अंदर कमरे में रखी एक प्लास्टिक की बोरी से प्लास्टिक रैपर में बंधे कुल 08 पैकेट बरामद हुए। जिसे गवाहों के स्पष्टीकरण जांच करने पर गांजा होना पाया गया। पुलिस द्वारा जब प्रभावित से गांजे के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया जा सका, जिस पर पुलिस ने प्रभावित राजकुमार दानी को हिरासत में ले जब्त गांजे का वजन किया गया, तो कुल वजन 8.250 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 04 लाख रुपये है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ थाना दुलदुला में अपराध क्रमांक 75/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया है। आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उनकी रही भूमिका

कार्रवाई व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुलदुला उप निरीक्षक सतीश कुमार सोनवानी, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र भगत सहित थाना दुलदुला पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मितजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के कारोबार एवं तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने थाना दुलदुला क्षेत्र में 08 किलो से अधिक अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। अग्रिम कार्रवाई जारी है।



शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल कोरना में पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत जशपुर द्वारा शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल, कोरना में पड़ोस के युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं एवं विद्यार्थियों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के अंतर्गत नशे के इकाइयां एवं नशा मुक्त समाज के महत्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। विद्यार्थियों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक नुकसान के प्रति जागरूकता करने हेतु जागरूकता वीडियो का प्रदर्शन भी किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष राजकुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं वक्ता के रूप में वी. बी. निराला, रामवृक्ष नाग, अजय चंद्रा एवं रीता मिंज ने युवाओं को निर्देशित किया। लाभार्थियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने, सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने तथा समाज में नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित अतिथियों, विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी ने स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। मेरा युवा भारत जशपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व, जन जागरूकता एवं सकारात्मक नेतृत्व की भावना विकसित करने के साथ-साथ नशा मुक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।

22 नवंबर को लगेगा मिर्गी ज्वार के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर, भोजन और फ़ोड़े की भी व्यवस्था

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। मिर्गी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए राहत से जुड़ी एक पहल के तहत 22 नवंबर 2026, रविवार को गम्हरिया स्थित अघोर पीठ वामदेव नगर आश्रम में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। बाबा भगवान राम ट्रस्ट, जशपुर द्वारा आयोजित इस शिविर में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। आयोजन को लेकर ट्रस्ट की ओर से तैयारियों की जा रही हैं।

21 नवंबर को ही आश्रम पहुंचे जरूरी

शिविरों में शामिल होने वाले मरीजों को 21 नवंबर, शनिवार को ही आश्रम पहुंचने की सलाह दी गई है। चूंकि दवा वितरण रविवार सुबह 4 बजे से शुरू होगा, इसलिए मरीजों को एक दिन पहले रात्रि विश्राम करना होगा। ट्रस्ट की ओर से मरीजों और उनके साथ आने वाले मरीजों के लिए मुफ्त भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है।

रोगियों के साथ एक सहयोगी लाना अनिवार्य

संचालकों ने शिविर में आने वाले प्रत्येक मरीजों के साथ एक सहयोगी को लाना अनिवार्य बताया है। नवंबर महीने में बढ़ती ठंड को देखते हुए मरीजों एवं उनके सहयोगियों को अपने साथ कंबल और बिछौना लाने की सलाह भी दी गई है, ताकि रात में टेंशन के दौरान परेशानी न हो।



समय और जरूरी सामान का ध्यान रखें

संचालकों ने मिर्गी रोग से पीड़ित मरीजों एवं उनके मरीजों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पहले आश्रम पहुंचने की तैयारी करें। रोगियों अपने साथ एक सहयोगी, कंबल और बिछौना अवश्य लेकर आएं।

गर्भवती महिलाओं के लिए दवा प्रतिबंध

ट्रस्ट की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि शिविर में वितरित की जाने वाली दवा गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दवा का सेवन नहीं करने की सलाह दी गई है।

सुबह 4 बजे से सूर्योदय तक मिलेगी दवा

बाबा भगवान राम ट्रस्ट एवं श्री सर्वेश्वरी समूह की ओर से जारी सूचना के अनुसार, शिविरों में फकीरी एवं आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार दवायां वितरित की जाएंगी। दवा वितरण का समय रविवार 22 नवंबर को सुबह 4 बजे से सूर्योदय से पूर्व तक निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के बाद दवा वितरण नहीं किया जाएगा।

बासनतला के प्रतिभागियों ने स्वच्छता अभियान चलाया, देहरादून को किया जागरूक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविरों के तीसरे दिन प्रतिभागियों ने सेवा, अनुशासन और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासनतला की एनएसएस इकाई के विद्यार्थियों ने शिविर के दौरान स्वच्छता अभियान चलाने के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

तीसरे दिन की शुरुआत प्रातःकालीन पीटी एवं व्यायाम से हुई। इसके बाद प्रतिभागियों ने विद्यालय परिसर और नवाटोली सड़क किनारे सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे उगी ग्वालियर, गंदगी और नालियों की सफाई की गई।

स्वच्छता अभियान चलाकर देहरादून को किया जागरुक

एनएसएस के प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का संदेश देते हुए कपड़ों को भी साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया। अभियान के माध्यम से लोगों को अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और सामुदायिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।



रंगारंग प्रस्तुतियों से बांधा समां

शिविरों के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने गीत, नृत्य और एकांकी की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार मंच पर प्रस्तुति देते हुए विद्यार्थियों ने उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, संगठनात्मक और सामूहिक सहभागिता की भावना देखने को मिली।

बौद्धिक चर्चा में दी गई एनएसएस की जानकारी

सांस्कृतिक गतिविधियों के बाद बौद्धिक चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संस्था के सचिव महेंद्र राम ने राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास, उद्देश्य और सामाजिक सरोकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को समाज सेवा, अनुशासन और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत दारा खारिका के पंच गणेश राम चौहान ने एनएसएस इकाई द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की सराहना की।

अतिथियों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे स्वयंसेवक

शिविर का संचालन परिसर एवं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद रसूल हसन खान के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। संस्था की शिक्षिकाओं रेशमा मिंज एवं रीना सहित अन्य दिशानिर्देशों का भी कार्यक्रम में सहयोग मिल रहा है। सात दिवसीय शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को ग्रामीण जीवन से जुड़ने, सामाजिक समस्याओं को समझने, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और समाज के प्रति अपनी प्राथमिकताओं का समाधान करने का अवसर मिल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को उनकी ही कर्मभूमि पर ललकारा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बीज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कर्मभूमि पर खड़े होकर सीएम पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नहीं बनवा सकता, चना नहीं बिकवा सकता, जो मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र की जनता को नौकरियां नहीं कर सकता, वह वोट चोरी करके ही सत्ता तक पहुंचा है। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बीज वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह जिले जशपुर में कांग्रेस की एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भाजपा पर जमकर असर डालना साधा। बीज ने कहा कि जो मुख्यमंत्री अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सड़कें नहीं बनवा सकता, किसानों की चना उपज नहीं बिकवा सकता, एथलीटों को गुड़ नहीं दिलवा सकता और नौकरियां नहीं कर सकता उसने वोट चोरी करके ही सत्ता हथियाई है।

बीज ने तंज कसते हुए कहा- भाजपा के बड़े-बड़े नेता कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो बिजली अनुमानित कम करवा देंगे, चकाक सड़कें बनवा देंगे, महंगाई कम कर देंगे। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। सड़कों का बेड़ागर्क हो गया है। कुंकुरी से यहां आते तक सड़क की दुर्दशा की त्रासदी मैंने स्वयं भोगी है। मुख्यमंत्री न तो किसानों को राहत दिलवा पा रहे हैं, न कपड़ों की बुनाई कर पा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, बिजली की अनुमानित संख्या बढ़ गई।



दीपक बैज ने कहा कि हमारा पानी, हमारा कोयला, सभी संसाधन हमारे, फिर भी हमें ही बड़ी महंगी बिजली दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला राज्य है, हमारी बिजली से कई राज्य रोशन होते रहे हैं, मगर दुख की बात यह है कि अब हमारा छत्तीसगढ़ ही दूसरे राज्यों से बिजली खरीदना मजबूर हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़े ही चुटीले अंदाज में उपस्थित जनसमुदाय से सवाल जवाब भी किया। उन्होंने किसी उपभोक्ता का 43 हजार का बिजली बिल लहराते हुए पूछा कि साय सरकार आने के बाद बिजली सस्ती हुई क्या? जनता ने जवाब दिया नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छे दिन के सपने दिखाने वाले मोदी सरकार के आने के बाद शक्कर, पेट्रोल डीजल और अन्य वस्तुओं के दाम घटे क्या? जनता का जवाब था बिल्कुल नहीं।

बैज ने कहा कि जो सरकारें बेईमानी और वोट चोरी के दम पर बनती हैं, वे जनता के साथ ऐसा ही छल करती हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सीधे चुनौती देते आरोप लगाया कि एक मुख्यमंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाना इस बात का बड़ा सबूत है कि भाजपा को प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासियों के विकास से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री की अनदेखी कर रही है। केवल आदिवासियों को खुश करने के लिए एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उन्हें काम करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी समाज को लेकर चलने की नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दर्रीपारा अंबिकापुर छ. ग. पिन नं. 497001 से मुद्रित व वार्ड क्र. 10 कुनकुरी जशपुर से प्रकाशित। संपादक - लक्ष्मण सिंह